ں۔ منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں
سے کی پیداوار کے بڑھنے اور گھٹنے کے سائیکل
کو کسی یونیفارم سطح پر لانے کے سمبندھ
میں کوئی پالیسی بنا رہے ہیں؟]

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** मैडम, जहां तक गन्ने की दावार है, पिछले कई वर्षों में मई तक मिलें चली हैं, पर स बार अभी तक उत्तर प्रदेश में हमारी 4-6 मिल चल ही हैं। 101 मिल 7 जुलाई तक चल रही थीं क्योंकि न्ना ज्यादा पैदा हुआ और क्रशिंग लेट तक करने का हम इंतजाम किया। हमें गन्ना किसानों को भुगतान करना ा। यह बैलेंस करने के लिए सम्यक रूप से इस पर चार किया जाएगा कि वह सायकिलक ऑर्डर में रहे योंकि टाइम से होने से इसके प्रोडक्शन पर भी और ष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोडक्शन है, उसका इससे संबंध जुड़ा आ है। हम इस पर सम्यक रूप से विचार करेंगे।

**श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** मैंने स्पेसिफिकली छा था कि शुगर डवलपमेंट फंड किसानों के लिए है रि आपने कहा कि रिकवरी बढ़ाएंगे, लेकिन आज सवाल कवरी का नहीं है। कई जगह रिकवरी अच्छी है और ई जगह नहीं है, लेकिन जो एक हजार करोड़ रुपया ापके पास है, वह किसानों का ही पैसा है। दूसरे किसी ा नहीं है।

जब ऐसी कठिनाइयां आ गई हैं तो उसमें टेम्परेरी लोन जरिए आप स्टेट गवर्नमेंट को मदद देने का प्रयास करें। र तरह का सुझाव मैंने रखा था। ऐसी चिट्ठियां महाराष्ट्र वर्नमेंट ने आपको लिखी हैं। मैं इतना ही आपसे कहूंगा ; आपकी मिनिस्टरी और आप खुद महाराष्ट्र का जो यह ानी का प्रश्न है उसमें ध्यान दें। यही मैं आश्वासन चाहता ।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** महोदया, यहां तक स॰डी॰एफ॰ का सवाल है, सुगर डवलपमेंट फंड का वाल है, माननीय सदस्य ने पहले यह चिंता जाहिर की और एस॰डी॰एफ॰ का मैंने पहले ही बताया था कि क्सपेंशन और मोडर्नाइजेशन पर ज्यादा इसमें लगाया ता है। जो भी आपके राज्य की डिमांड आई होगी और हां तक मिलों की स्थिति का है, मैं तो समझता हूं कि ापके यहां महाराष्ट्र में 110 मिल हैं और इन 110 मिल 104 तो सहकारी मिल हैं, शेष 6 मिल बचती हैं। इसमें सहकारी मिल हैं उसकी क्या स्थिति है, आप एक्सपेंशन के लिए मोडर्नाइजेशन के लिए कि बावत एस॰डी॰एफ॰ से पैसा चाहते हैं, उसको स्पष्ट करके आप भेजें। यदि एस॰डी॰एफ॰ के केस की कोई चीज हमारे पास होगी, इसमें मैं समझता हूं कि मैं इसको देख लूंगा और आपका क्या प्रस्ताव है इस पर मैं विचार करुंगा इस दृष्टि से।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I hope that the Members who have participated in the Calling Attention Motion are quite satisfied with the answer. We shall now take up the Private Members' Resolution.

---

## PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

### Resolution for Evolving a mechanism to Tackle Corruption

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): It is going to be quarter past three.

We will have it for two-and-half hours from now. Shri Ramdas Agarwal.

**श्री रामदास अग्रवाल** (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी इजाजत से जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था, उसको और अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने की दृष्टि से उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करने की इजाजत आपसे चाहता हूं और वह टैस्ट इस प्रकार से है, जो मैं आपके सामने पढ़कर आपकी अनुमति के बाद बोलना चाहूंगा:—

> "Having regard to the fact that corruption is increasing day-by-day endangering democracy and lowering the political and ethical standards, this House resolves that there is an imminent necessity to evolve a mechanism to tackle the problem."

मुझे आशा है कि आप इसकी इजाजत देंगी।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** क्या सदन इस चीज की इजाजत देता है?

**एक माननीय सदस्य :** जी हां।

**श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान) :** हां जी, कोई आपत्ति नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** धन्यवाद। बोलिए, रामदास अग्रवाल जी।

SHRI RAMDAS AGARWAL: Madam, I move:

---

ransliteration in Arabic Script

"That having regard to the fact that corruption is increasing day-by-day endangering democracy and lowering the political and ethical standards, this House resolves that there is an imminent necessity to evolve a mechanism to tackle the problem."

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मुझे संकल्प प्रस्तुत करने का, 6 साल के मेरे सांसद के जीवन में, पहली बार मौका मिला है। मैं आपका आभारी हूं। मैं जब 1990 में इस सदन का सदस्य बनकर आया तो मुझे इस बात का बड़ा गौरव और गर्व अनुभव हुआ कि मैं इस सम्मानित संसद का सदस्य बनने जा रहा हूं। मेरे मन में यह कल्पना थी कि संसद में, जहां देश के सम्मानित, देश के संभ्रांत, सुजान और योग्यतम व्यक्ति निर्वाचित होकर आते हैं और जिन पर देश का नेतृत्व करने का, देश का संचालन करने का भार रहता है उन लोगों के बीच में बैठकर, मुझे कुछ ऐसी बातें करने का अवसर मिलेगा, जिससे देश के अंदर जो विपदाएं और कठिनाइयां पैदा हुई हैं उनका समाधान मिले।

महोदया, यह केवल मेरा ही विचार नहीं था, जिस समय भारत आजाद हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय जिन महानुभाव ने, जिन महापुरुषों ने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया उनका भी विचार था, उसमें चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों, गोखले रहे हों, सुभाष चन्द्र बोस रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, जवाहर लाल नेहरु रहे हों, डा॰ श्यामाप्रसाद मुखर्जी रहे हों, आचार्य कृपलानी रहे हों, डा॰ अम्बेडकर रहे हों। महोदया, मैं आज इस बात को इसलिए याद करना चाहता हूं क्योंकि जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है वह मैंने आलोचनात्मक दृष्टि को सामने रखकर प्रस्तुत नहीं किया है, मैंने उसमें परिवर्तन भी कुछ जानबूझ कर किया है।

मैं ऐसी बहस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, अपने माननीय सदस्यों के सामने कि हम उस सपने को, उस कल्पना को याद करें कि भारत को आजादी दिलाने वाले लोगों के मन में जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, भारतवर्ष की क्या कल्पना थी और आज आजादी के 50 वर्ष बाद क्या हम भारतवर्ष का चित्र उनकी कल्पना अनुकूल बना पाए हैं? यह एक आलोचना का सवाल नहीं है, लेकिन यह आत्म-चिंतन, मंथन और विवेचन का विषय है। यदि हम सब यह अनुभव करते हैं कि हमने महात्मा गांधी और हमारे देश के उन महान सपूतों की कल्पना के अनुसार भारत की रचना कर ली है, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बहस समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, मेरे इस विचार से सदन भी सहमत होगा, कि वे कल्पनाएं केवल कागजी रह गई हैं, वह कल्पनाएं अधूरी रह गई हैं, वे सपने साकार नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं? उसके कारण ढूंढने पर हम पचासों वह के विषय निकाल लेंगे, हम तर्क-वितर्क कर सकते हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, एक-दूसरे के चेहरे पर कालिख पोत सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य का निर्माण इससे नहीं हो सकता। इसलिए, महोदया, मैंने यह विषय जान-बूझकर आज सदन के सामने रखा है कि उन महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप देश का निर्माण करने में हम क्यों सफल नहीं हुए, हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि यह हुआ क्यों नहीं? संसद मौजूद थी, सांसद मौजूद थे, गवर्नमैंट मशीनरी मौजूद थी, पैसा मौजूद था, कर्जा लिया गया था, मंत्री थे, प्रधान मंत्री थे, प्रशासनिक मशीनरी थी, सब कुछ था इस देश में, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज हम महात्मा गांधी के उस "राम राज्य" की कल्पना से चलते-चलते "बैंडिट क्वीन" के राज तक आ गए हैं। आज हम उस कल्पना से चलते-चलते, जहां इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, निमर्म हत्या हुई थी, नयना साहनी हत्याकांड तक पहुंच गए हैं। यह क्या हमारी तरक्की का रास्ता है जिस पर चलने का विचार किया था? क्या यह कल्पना थी हमारी कि हम अपने देश को इस स्तर तक पहुंचाएंगे? जहां पंडित नेहरु के समय पर केवल 10,000 के घोटाले पर —जो केशव देव मालवीय पर, उनके केन्द्रीय मंत्रि-मंडल के माननीय सदस्य पर सदन में आरोप लगा, किसी अखबार में आया—पंडित जवाहर लाल नेहरु ने देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के नैतिक मूल्यों को कायम करने के लिए, देश की नैतिकता को बरकरार रखने के लिए एक छोटी-सी इंक्वायरी कराकर अपने मंत्रि-मण्डल से केशव देव मालवीय को हटा दिया था। यहां बहुत सारे बंधु हैं जो उन्हें मानते हैं।, देश के प्रधान मंत्री के नाते मेरी भी उनमें श्रद्धा है और मैं यह ऐप्रिसिएट करना चाहता हूं कि उन महानुभावों ने देश के अंदर नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए अपने मंत्रि-मंडल के अपने निकटतम सहयोगी को केवल 10,000 रुपए के लिए मंत्रि-मंडल से बर्खास्त कर दिया था और आज 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने के बाद भी कोई मंत्री त्याग-पत्र देने को तैयार नहीं, आज कोई प्रधान मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। एक-एक घोटाले की चर्चा मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नैतिक मूल्यों का ह्रास इस देश में कितना हो गया है। हम कहां जाना चाहते हैं? आखिर यदि इस देश की राजनीति को हम ऐसे स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां पर रक्षक भक्षक बन जाएं, जहां पर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, जहां पर कितना भी

हल्ला मचाएं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं, तथ्यों से लगाएं, वास्तविक लगाएं, सच आरोप लगाएं, सच आरोप साबित हो जाएं, उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती।

उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती मानो कान में तेल डाल कर बैठे हों। सरकार सुनना ही नहीं चाहती। हर आदमी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहा है। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि देश के किसी भी भाग में रहने वाला व्यक्ति किसी पर भी खुलेआम आरोप लगा सकता है और आरोप कितना झूठा है, कितना सच्चा है, इसका पता नहीं लेकिन आज केवल आरोप लगाने की भाषा का इस्तेमाल होता है।

महोदया, रोज सुबह हम अखबार पढ़ते हैं, बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार का आरोप किसी प्रदेश में लग रहा है, कहीं दिल्ली में लग रहा है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम सबने एक दूसरे के मुंह पर कालिख पोतने का काम तो कर लिया। अब इस देश के अंदर राजनीतिज्ञों में से ईमानदार राजनीतिज्ञ को ढूंढना कितना कठिन है, यह हम सब जानते हैं। आखिर राजनीतिज्ञों की यह स्थिति क्यों बन रही है? आखिर हम पर इस प्रकार के आक्षेप क्यों लग रहे हैं? आखिर न्यायालय आज राजनीतिज्ञों को कटघरे में खड़ा करके क्यों उनसे और चीजें उगलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्यों नहीं प्रशासनिक मशीनरी ने अपना काम किया? क्यों नहीं प्रशासनिक तंत्र ने, विधायिका ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? क्यों नहीं होंने लोगों को सजाएं दीं? क्यों नहीं उन्होंने अपराधियों को कटघरे में खड़ा किया? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्यवाही की?

महोदया, जब कार्यवाही नहीं हुई तो लोगों ने सीधे न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए। तो फिर न्यायालयों ने विधायिका के काम में हस्तक्षेप किया। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। यह बहस दूसरे सदन में चल रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायालयों ने हमारे काम में क्यों हस्तक्षेप किया? इसलिए किया कि विधायिका अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थ रही। जिस सरकार पर यह दायित्व था, वह सरकार अपने फर्ज को अंजाम देने में असफल रही और इसी के कारण सुप्रीम-कोर्ट में एक केस के मामले में जजों को कहना पड़ा कि सी॰बी॰आई॰ सीधे हम लोगों को रिपोर्ट करे। वैसे सी॰बी॰आई॰ प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है। लेकिन सुप्रीम-कोर्ट को कहना पड़ा कि सी॰बी॰आई॰ आगे से इन मामलों में सीधे सुप्रीम-कोर्ट को जवाब देगी। यह क्या मजाक है? देश में शासन इस तरह से चल सकता है क्या? क्या देश के अंदर प्रशासन इस ढंग से चलाया जा सकता है? क्या देश को सही ढंग से नेतृत्व दिया जा सकता है इस प्रकार से?

कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके कामों में अगर कहीं दखल होता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई न कोई खामी, कोई न कोई कमजोरी अवश्य उत्पन्न हो गई है। महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर विधायिका का जो कार्य है वह इतना कमजोर बन गया है, इतना निकम्मा बन गया है, इतना अक्षम बन गया है कि वह किसी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ है। मुझे प्रशासन की यह मजबूरी समझ में नहीं आती। आखिर क्या वजह है कि हमारे पास सब कुछ अधिकार होते हुए भी देश के अंदर बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार और सभी प्रकार के गलत आचार बढ़ रहे हैं? यह स्थिति क्यों बन गई है? हमारे पास सब ताकत है, हमारे पास पूरी क्षमता है लेकिन क्षमताओं के होने के बावजूद इस देश के अंदर आज स्थिति ऐसी बन गई है कि देश का हर आदमी आज ब्लैक-मार्केटियर बनता दिखाई दे रहा है। उसे यदि चीनी खरीदनी है तो ब्लैक-मार्केट से खरीदनी पड़ती है। उसे अगर कोर्ट में जाकर तारीख निकलवानी है तो भ्रष्टाचार करना पड़ता है। उसे किसी दफ्तर में जाकर कोई काम करवाना है तो उसे रुपया खर्च करना पड़ता है।

महोदया, आज जीवन के हर अंग में, सामाजिक व्यवस्था के हर ढांचे में भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया है। मैं स्कैम्स की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं स्कैम्स की बात करुंगा तो फिर वही बातें दोहराई जाएंगी। महोदया, पिछले 5-6 बरसों में हमने इतने स्कैम्स देख लिए हैं कि अब स्कैम के नाम से घृणा होने लगी है। किसी भी स्कैम की बात हम देखें। दस हजार करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हो गया।

महोदया, सिक्योरिटी स्कैम हो गया और यह तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि संसद ने जोइंट पार्लियामेंट्री कमैटी बनाई कि जो घोटाला हुआ है उनके बारे में जांच की जाए, जांच करने के बाद अपराधियों को सजा दी जाए, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको दंड दिया जाए। लेकिन महोदया, जे॰पी॰सी॰ की रिपोर्ट आए कई महीने हो गए लेकिन अभी तक उसके बारे में केवल कार्रवाई की चर्चा चलती है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम लोगों को सजा देंगे, ऐसा संकल्प बार-बार सदन को दिया जाता है, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो लोग इसीलिए परेशान हैं, लोग इसीलिए दुखी हैं, लोग इसीलिए निराश और हताश हैं। अगर न्याय लेना है,

किसी को सजा दिलानी है उसके अपराध की, तो यह विधायिका नहीं दे सकेगी, शायद यह संसद भी नहीं दे सकेगी इसलिए वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है। आखिर यह स्थिति क्यों आई। महोदया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। अगर इस वातावरण को बदला नहीं गया तो मुझे डर है कि मैं भी उनमें से राजनीति में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं, मुझे डर है इस बात का कि हमारा यह प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हम लोग जनता के सामने मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। गलत काम कोई और करेगा और परिणाम किसी दूसरे को भुगतना पड़ेगा। सब बेइमान नहीं हो सकते, सब चोर और भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस देश के अंदर इतिहास साक्षी है कि अगर रावण पैदा हुआ था तो राम भी पैदा हुआ, अगर कंस पैदा हुआ था तो कृष्ण भी पैदा हुआ और यदि अनाचार बढ़ा था तो बुद्ध भगवान और महावीर भगवान पैदा हुए थे इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता अपने देश के बारे में, इस महान देश के बारे में कि सभी लोग अब बेईमानी की ओर बढ़ गए हैं। इस देश के अंदर ईमानदार लोग बहुत हैं। ईमानदार लोग चाहते हैं कि हमारी ईमानदारी बरकरार रहे, ईमानदार लोग चाहते हैं कि हमारा प्रशासन स्वच्छ बने, ईमानदार लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है वह ईमानदारी से खर्च किया जाए। लेकिन मुझे दुख है कि वास्तविकता से दूर हटकर और हमारे यहां पर मुझे याद आता है राजीव गांधी जी राजस्थान गए थे.....(व्यवधान)....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) : Mr. Minister silence please.

**श्री रामदास अग्रवाल:** शायद मंत्री जी के मतलब की बात नहीं है क्योंकि नैतिकता का मामला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने राजस्थान के उदयपुर में एक बात कही थी। कांगेस के सब बंधु इस बात के साक्षी हैं हमारे शीशराम जी भी बैठे हैं, उनको भी पता है। उन्होंने यह कहा था कि जो एक रुपया दिल्ली से चलता है वह कंज्यूमर तक पहुंचते-पहुंचते, उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते, नागरिक तक पहुंचते-पहुंचते वह केवल 15 पैसे रह जाता है, 85 पैसा डकार लेते हैं, 85 पैसा हड़प लिया जाता है, कुछ लोगों की जेब में चला जाता है। वह राजनीतिज्ञ भी हैं, वह सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वह प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी भी हैं। उन सब की जेबों में वह पैसा चला जाता है और जब वह पैसा चला जाता है तो फिर वह क्या काम करेगा? वह अपराधियों को पैदा करेगा। यह क्या हुआ-चोरी का पैसा आपराधीकरण की प्रवृत्ति को विकसित करेगा, यह क्या हुआ-वह पैसा समाज के अंदर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का काम करेगा जो आज प्रत्यक्षतम् देख रहे हैं। महोदया, आज हम देख रहे हैं कि राजनीति में अपराधीकरण की कितनी बड़ी भूमिका हो रही है। आज अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच में किस प्रकार से वोहरा कमेटी ने रिमार्क्स दिए हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के लिए ऐसा कोई समय हो सकता है, ऐसी शर्मनाक स्थिति मैंने किसी सरकार की नहीं देखी कि जिसके अधिकारी यह कहें कि राजनीति में, सत्ता में रहने वाले लोगों का अपराधियों के साथ सांठगांठ है और देश के अंदर अगर अपराध बढ़े हैं, अपराधियों के गैंग्स बढ़े हैं, असामाजिक तत्वों की कार्यविधियां बढ़ी हैं तो उसके कारण ही राजनीतिज्ञ लोग उनको संरक्षण देते हैं। राजनीतिज्ञ अगर संरक्षण देगा तो जैसा मैंने कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो इस देश को कौन बचाएगा। महोदया, अगर स्मगलिंग हो करके ए॰के॰ 47 या ए॰के॰ 57 और ड्रग्स आ सकते हैं, हवाई जहाज के द्वारा ऊपर से हथियार गिराए जा सकते हैं। तो इसे देश के अंदर फिर क्या बचेगा।

आखिर हम सब महानुभाव जो सांसद में बैठते हैं, उन सब के लिए यह बड़े गंभीर चिंतन का विषय है कि क्या इस देश के अंदर ये सब गतिविधियां चलनी चाहिएं? क्या भ्रष्टाचार चलना चाहिए? क्या नौजवान को हताश, निराश होकर घर बैठ कर असामाजिक तत्वों के साथ मिल कर समाज में काम करना चाहिए? क्या उसको हम रास्ता नहीं दिखाएंगे? क्या हम उसको सही रास्ते पर नैतिकता दिख कर देश का अच्छा नागरिक नहीं बनाएंगे? क्या हम इसी प्रकार से लगातार भ्रष्टाचारों की बौछार एक-दूसरे पर करते रहेंगे? कलंकित करते रहेंगे राजनीति को, राजनेताओं को? क्या इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है?

महोदया, मैं बहुत सारे तथ्य दे सकता हूं जो किताबों में लिखे हुए हैं। मैंने जितनी बातें आपके सामने कही हैं मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। मुझे आश्चर्य हुआ है, अभी यह सरकार जुम्मे-जुम्मे चार दिन की सरकार है और इस सरकार के बनते ही यह कोजैन्ड्रिक्स का मामला आ गया। इनके ही सांसदों ने आरोप लगा दिया। मैंने नहीं लगाया, मेरी पार्टी ने प्रधान मंत्री पर आरोप नहीं लगाया क्योंकि हम समझते हैं कि अभी आए हैं, उनको बैठने चाहिए, उनको उचित अवसर देना चाहिए। उनके कारनामे कर्नाटक में जो रहे होंगे, उसकी हमने चर्चा नहीं की। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते, एक उत्तरदायी पार्टी के नाते हमने अपने दायित्व को निभाया है लेकिन उन्हीं के

पार्टी के लोग उन्हीं के प्रधानमंत्री को न जाने क्या-क्या कह रहे हैं? हम नहीं चाहते हैं ऐसा। हम चाहते हैं कि आखिर एक नई सरकार बनी है, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि इनके मंत्रिमंडल में पांच-सात लोग हैं जिन पर आरोप हैं, उन पर हत्या के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, उनके ऊपर न जाने किस-किस प्रकार के असामाजिक कार्यकलापों के आरोप हैं? मुझे आश्चर्य होता है। एक मंत्री को तो जाना पड़ा इसीलिए। महोदया, यह क्या है कि इस देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बन गई है और हम भ्रष्टाचार की बात जब करते हैं तो एक ओर सबसे ज्यादा शर्मनाक जिसे मैं कहना चाहूंगा, वह हत्याकांड हुआ था हमारे देश के एक प्रदेश में जिसका नाम बिहार है। बिहार के अंदर बेचारे जो बोल नहीं सकते, हमारा आज राशन कट जाए तो हम बोल सकते हैं, आज हमें खराब चीनी, खराब अनाज मिले तो हम सदन में आ कर चिल्ला सकते हैं, आज हमें बिजली, पानी न मिले तो हम रो सकते हैं आपके सामने आकर लेकिन वे बेचारे पशु जिनके चारे में पैसा खा गए, इससे ज्यादा पतन इस देश में राजनीति का और क्या होगा? इससे अधिक पतन और कहां जाएगा? कौन सी सीमा होगी पतन की? ... (व्यवधान)...

**श्री सनातन बिसि (उड़ीसा)** : मैडम, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री:** मेरा एक प्वाइंट ऑफ इनफार्मेशन है।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : इसमें एक प्वाइंट ऑफ इनफार्मेशन है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अपनी बात बोलने की बिलकुल आज़ादी है। चारे का सवाल नहीं है, सवाल है जो ट्रेज़री है, उसकी लूट हुई है। मतलब जालसाज़ी से पेमेंट लूट लिया है अधिकारियों ने। बिहार सरकार ने चालीस लोगों को ...(व्यवधान)...

**श्री रामदास अग्रवाल** : हिन्दी में श्लेषार्थ ढंग से भी कुछ बातें कही जाती हैं जो सीधी समझी जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पशुओं का चारा ...(व्यवधान)... पशुओं का चारा तो आप नहीं खा सकते। ...(व्यवधान)...

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : पूरे देश में आपकी बात जा रही है इसलिए इस जानकारी को सही-सही रूप में रखा जाए, यही मैं कह रहा हूं।

**श्री सनातन बिसि** : मैडम, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर था।

SHRI SANATAN BISI: Madam, a point of order. This matter cannot be mentioned because this is sub-judice. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Where is the question of point of order?

SHRI SATISH AGARWAL: He is only making a passing remark. He is not going into the merits of the case. (*Interruptions*) He is only citing certain incidents like fodder scam ....(*Interruptions*)....

**श्री रामदास अग्रवाल** : सब-ज्यूडिस के नाम पर बचने की कोशिश मत कीजिए। मैंने ऐसा कोई मामला नहीं कहा है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Bisi, you yourself are a very renowned lawyer and you know it.

SHRI SANATAN BISI: Madam, I have not submitted anything wrong.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): But the hon. Member has not said anything wrong. He was just making a passing remark. Why there should be any misunderstanding?

**श्री रामदास अग्रवाल** : महोदया, मैंने जो आपके सामने निवेदन किया मेरा सीधा अर्थ यह है कि आज जिस प्रकार के घोटाले, महाघोटाले, भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार की श्रृंखला बन गई है उसका कहीं अंत नहीं हो रहा है। महोदया, शेयर घोटाले के समय इस देश की सरकार ने उस समय कठोर कदम उठा लिये होते और अपराधियों को कानून के मुताबिक सरेआम सजा दी होती तो शायद इस देश के अन्दर दूसरे घोटाले नहीं होते। अगर बोफोर्स काण्ड में इन्वाल्व लोगों को देश में लाकर सजा दे दी होती तो शायद यह बैंक काण्ड भी नहीं होता और यदि बैंक काण्ड में भी हमने किसी को सजा ठीक प्रकार से दे दी होती, एक्जम्पलरी ट्रीटमेंट कर दिया होता, पनिशमेंट दे दिया होता तो फिर शुगर स्कैम नहीं होता, हवाला काण्ड नहीं होता, यूरिया काण्ड नहीं होता।

महोदया, आखिर गिरने की सीमा कहीं तो तय होनी चाहिए। मैं मान सकता हूं कि बोफोर्स काण्ड में दलाली दी गई होगी, लोग-बाग दलाली लेते हैं यह मान लिया। मैं

उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, परन्तु इस देश की सभी पार्टियों ने और इस देश के बहुत सारे इन्क्वारी करने वाले लोगों ने माना है कि इसमें दलाली ली गई। महोदया, यहां तो सारा का सारा 133 करोड़ रुपये डकार लिया। माल आना था 133 करोड़ रुपये का लेकिन एक भी पैसे का माल नहीं आया। ये भ्रष्टाचार के बढ़ते हुये कदम हैं जो हमारे देश को चूस रहे हैं, जो हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, हमारे देश के धन को न जाने कहां ले जा कर रख रहे है? मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि एक सौदा किया जाता है, उसका एडवांस दिया जाता है और माल आयेगा एक साल के बाद। पहले कहा गया था कि दो महीने में आ जायेगा लेकिन बाद में कहा गया कि एक साल का अमेंडमेंट कर दिया गया है लेकिन पैसा तुरन्त दे दिया जाता है, उसमें से दलाली का पैसा भी आ जाता है और हमारे देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा इस देश के बाहर चली जाती है और न जाने किन-किन खातों में बंट गई है। महोदया, हमने इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई और यदि हमारे इन लोगों में चाहे वह राजनीतिज्ञ हों, चाहे वह अफसर हों, चाहे सरकारी प्रतिष्ठानों के अधिकारी हों, यदि उन पर रोक नहीं लगाई, उनको चैक नहीं किया गया और यदि उनके घृणित कार्यों की सजा नहीं दी गई तो क्या ये काण्ड रुक सकेंगे? कौन रोक सकता है और कहां रोकेंगे? जिसकी छोटी-बड़ी 14 टांगे हैं यह कहां से रोक पायेगी? जो 260 लोगों की सरकार जीतकर आई थी वह नहीं रोक पायी और जो 424 लोग राजीव गांधी के समय में लोक सभा में जीत कर आये थे, वे भी रोक नहीं पाये तो यह 44 लोगों की सरकार कैसे रोक पायेगी? उस समय राजीव जी को कहना पड़ा कि एक रुपये में से 85 पैसे लोगों की जेब में चले जाते हैं, जनता के पास 15 पैसे पहुंचते है। यह छोटी-बड़ी टांगों की सरकार है, इसकी अगर 14 टांगे समान होतीं तो भी मेरी समझ में आ जाता। लेकिन इसकी कोई टांग तो 143 की बहुत बड़ी है और कोई चार लोगों की टांग बहुत छोटी है तो क्या इसमें कोई समानता है, कहीं इसमें चलने की क्षमता है, यह कैसे चलेगी यह मेरी समझ में नहीं आता है? मेरा सभी सांसद बन्धुओं से निवेदन है कि देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार अपनी सीमा पार कर चुका है और यदि हम और आप नहीं चेतेंगे तो इसके परिणाम हम सबको भुगतने पड़ेंगे। हम सभी सांसदों को ऐसे काण्डों को रोकने का एकजुट होकर संकल्प लेना चाहिए। चाहे वह किसी भी दल के हों, चाहे सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार को रोकने का नैतिक दायित्व हम सभी का है।

महोदया, एक पाइन्ट और है जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा जवाहर लाल नेहरू जी के समय में या लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में यदि कोई काण्ड हो जाता था तो मंत्री सीधे जिम्मेवारी लेता था। जब श्री कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे तो उन पर चार्ज आया कि देश की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। वे नेहरू जी के परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे तब भी नेहरू जी को दबाव में आकर उनको हटाना पड़ा, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल था। देश के अन्दर गड़बड़ी न हो जाये इसका सवाल था। महोदया, इसी प्रकार से आज हमारे सामने सवाल आ गया है।

लेकिन आज हमारे सामने सवाल आ गया है कि किसकी जिम्मेदारी है। इतने हजारों करोड़ रुपये के घोटाले होते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की एकाउन्टेबिलेटी नहीं है, कोई यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हां, यह मेरे द्वारा हुआ था, इसलिए मुझे सजा दो। अगर हम किसी अपराधी को पकड़ भी लेते हैं तो वह कोर्ट में जाकर, वहां खड़ा होकर कहता है कि वह सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा, वहां जाकर कितना झूठ बोलता है यह भगवान जाने। वह साफ मना करता है। यह अजीब स्थिति है। कानून उनको पकड़ नहीं सकता, हमारा प्रशासन उनको पकड़ नहीं सकता। सरकार में उनको पकड़ने की संकल्पशक्ति नहीं है। आखिर इन अपराधियों को कौन पकड़ेगा? यह सारी संसद बैठी रहेगी, सारे संसद सदस्य बैठे रहेंगे, देश का लोकतंत्र बैठा रहेगा, देश की सरकार बैठी रहेगी और इस प्रकार के कांड होते रहेंगे, भ्रष्टाचार के कांड होते रहेंगे, हत्याकांड होते रहेंगे, बलात्कार-व्यभिचार होते रहेंगे और हम चुपचाप बैठे-बैठे देखते रहेंगे। इन चीजों को देखना पड़ेगा।

**श्री मोहम्मद सलीम** (पश्चिम बंगाल) : मैं, रामदास जी, आपके भाषण से बहुत प्रेरित हुआ। भाषण तो हम यहां कर सकते हैं लेकिन इसको किस तरह से करें यह भी हमें देखना पड़ेगा। रामदास जी, राजस्थान में आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोग सड़कों पर हैं। वे हुकूमत से सिर्फ ट्रांसपरेंसी कुछ मुद्दों पर चाहते हैं। मैं घोटाला तो नहीं कह सकता, बुरी बात है लेकिन वह ट्रांसपरेंसी चाहते हैं। लेकिन वहां आप यह नहीं करते। वहां के पी.डब्लू.डी. मिनिस्टरी के बारे में जहां ह्यूमन राइट्स संगठन के लोग सड़कों पर हैं। आप ट्रांसपरेंसी चाहते हैं लेकिन अपने काम काज में वहां आपकी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। आप उनको तैयार कीजिए।

†شری محمد سلیم: میں رام داس جی اپنے بھاشن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ بھاشن تو ہم یہاں کر سکتے ہیں لیکن اسکو کسطرح سے کریں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ رام داس جی راجستھان میں آپکی سرکار چل رہی ہے۔ وہاں کے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ وہ حکومت سے صرف ٹرانسپیرنسی کی مانگ پر جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا کو نہیں کہہ سکتا بڑی بات ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں آپ یہ نہیں کرتے۔ وہاں کے بی۔جے۔پی۔ ڈی۔ منسٹر کے بارے میں جہاں "مزدور راشٹریہ کمیشن" کے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ آپ ٹرانسپیرنٹ کیجئے اپنے کام کاج کو۔ لیکن وہاں آپکی سرکار نہیں کر رہی ہے۔ آپ اسکو تیار کیجئے۔

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला (पंजाब) : वह वहां की सरकार की पार्टी के प्रधान हैं। ये यह कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि वे राजस्थान बी.जे.पी. के प्रधान हैं। ...(व्यवधान)...

†شری محمد سلیم: میں نے اسی لئے بولا ہے کیونکہ وہ راجستھان بی۔جے۔پی۔ کے پردھان ہیں۔۔۔

SHRI SATISH AGARWAL: Mr. Salim, the issue that Mr. Ramdas Agarwal has raised in this House is not concerned with parties.

SHRI MD. SALIM: No, no I do not blame them.

SHRI SATISH AGARWAL: Why are you diverting the whole issue to Rajasthan, to West Bengal. He has not referred to the scandal of WAKF properties in Bengal. He is not referring to that.

SHRI MD. SALIM: This is right. It is not true. That is why we have asked for a judicial enquiry.

SHRI SATISH AGARWAL: So it is across party barriers.

†[ ]Transliteration in Arabic Script

SHRI MD. SALIM: We have seen the list in the Hawala *Kand* across party lines.

SHRI SATISH AGARWAL: So is his premises of argument.

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, मैंने प्रारंभ में ही यह निवेदन किया था कि मैं किसी के ऊपर डाइरेक्ट किसी तरह का लांछन लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास भी बहुत मैटीरियल है। बंगाल सरकार के बारे में भी और बाकी सरकारों के बारे में भी। लेकिन मैं आज विशेषरूप से केवल संसद में एक आम सहमति का भाव पैदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस भावना के लिए आप सबका आभारी हूंगा। इस पर कोई राजनीति की बू नहीं आनी चाहिए ऐसा मैं चाहता हूं। मैं यहां पर किसी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हमें इस देश में आर्थिक परिवर्तन लाकर इस देश का निर्माण करना है, प्रजातांत्रिक माध्यम से करना है, प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से करना है तो आप और हम सब को मिलकर इसे करना है। लेकिन अगर हम कलमुंहे कहलायें, हमारे ऊपर आक्षेप होते रहें, आरोप लगते रहे और हर गली कूचे में आदमी जाने-अनजाने में हम पर बेईमानी के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाते रहें तो आपका और हमारा चेहरा कहां से उजला रहेगा। अगर हमें अपना चेहरा उजला रखना है - मैं दूसरे विषय पर आ रहा था लेकिन आपने बीच में बोल दिया।

मैं यह कहना चाहता हूं और पहले मैंने आपके सामने निवेदन किया कि एकाउन्टेबिलिटी आज इस देश के अंदर नहीं है। अगर कोई भी सरकारी अफसर चाहे वह किसी कंपनी का मैनेजिंग डाइरेक्टर हो, चेयरमैन हो या और कोई भी अधिकारी रहा हो, चाहे परचेज मैनेजर हो चाहे कोई हो, अगर उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है तो जो कुछ भी गड़बड़ियां उसके कार्यकाल में हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी उसी पर थोपी जानी चाहिए। अभी परसों ही उज्जैन में इतने लोग मरे। मेरी यह बात समझ में नहीं आई कि इसके लिए जो जिम्मेदार अफसर था उसका केवल ट्रांसफर हुआ। इतने लोग मर गए और आफिसर का ट्रांसफर हो गया और वह ट्रांसफर भी अगर उज्जैन से बड़ी जगह पर हो गया हो तो उसको रिवार्ड मिल गया। यह माजरा क्या है? आखिर इतने लोग मरे तो उसके लिए आपने कदम तो उठाने चाहिए थे कि आगे भविष्य में कोई इस तरह न कर सके।

ऐसी अव्यवस्था के कारण कोई आदमी अपनी जान न दे दे, तीर्थ यात्रा करने गया आदमी वहां मर जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए क्या होगी? क्यों नहीं व्यवस्था की जा सकती थी? लेकिन ट्रांस्फर से अकाऊंटेबिलिटी नहीं होती। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाऊंटेबिलिटी का मतलब है जब तक वह जिन्दा है तब तक उसके ऊपर किये गये काले कारनामे की जिम्मेदारी रहेगी और उसको तब तक सज़ा दी जाएगी जब तक वह नौकरी में रहेगा या ज़िन्दा रह कर पेंशन लेता है। पूरी अकाऊंटेबिलिटी होनी चाहिये। उसको छोड़ नहीं देना चाहिये। उसको ट्रांस्फर नहीं कर देना चाहिये। जे.पी. सी. में बहुत लोगों को ट्रांस्फर कर दिया गया। यूरिया कांड में जो सारे लोग शमिल थे उनमें से दो-चार को पकड़ लिया और बाकी लोगों का छोड़ रखा है। जिनके ऊपर अकाऊंटेबिलिटी होनी चाहिये, यह ऐसे मुद्दे है। यदि अकाऊंटेबिलिटी निर्धारित नहीं की गई तो कोई भी कांड होगा उसकी जिम्मेदारी न मंत्री लेगा, न सांसद लेगा, न एम.एल.ए. लेगा, न मुख्य मंत्री लेगा और राजनीतिक लोग पकते चले जाएंगे, राजनीतिक लोग अपना अखाड़ा चलाते रहेंगे, अपनी नेतागिरी चलाते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे भ्रष्टाचार में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं महोदया कि आखिर अकाऊंटेबिलिटी के बारे में संसद को निर्णय करना है। दूसरी बात जो आपके सामने सलीम साहब ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी राज्य सरकार हो या कहीं पर भी काम करने वाले लोग हों, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो राज्य सरकार उससे निबटने के लिए सक्षम हो सकती है, उनके यहां मेकेनिज्म होगा लेकिन यदि कोई ऐसा बड़ा चार्ज आता है तो केन्द्र में भी इसके बारे में जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही के लिए कदम उठाया जा सकता है। सबके लिए यह खुला हो। सब को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। इस राजनीति को अपराधियों ने छा दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। महोदया, एक दिन आएगा अगर हमने अपराधियों को संसद में आने से नहीं रोका, अगर हमने कानून नहीं बनाया, अगर हमने संविधान के अन्दर परिवर्तन नहीं किया तो फिर अपराधी जीत सकता है, लड़ सकता है। चुनाव लड़ता है तो जीत भी सकता है। जीत सकता है तो सांसद बन सकता है। जब वह सांसद बन जाएगा तो मंत्री भी बन सकता है। कौन रोक सकता है? मैं चुने हुए सांसद के बारे में नहीं कह सकता कि कल यह एक डाकू था। मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं कहना चाहिये क्योंकि वह मेरा सहयोगी है।

**श्री मोहम्मद सलीम:** वह अगर पकड़ा जाए, जेल में चला जाए तो उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं ... (**व्यवधान**)...

†श्री मोहम्मद सलीम: वह अगर पकड़ा जाए, जेल में चला जाए तो उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं ... (व्यवधान)...

**श्री रामदास अग्रवाल:** यह भी ठीक है यानि हम रिवार्ड देते हैं। पति जेल में और पत्नी पार्लियामंट में, यह कौन सा हिसाब है? (**व्यवधान**) पति जेल में और पत्नी पार्लियामेंट में, वही तो मैं कह रहा हूं। यह कोई न्याय नहीं है। यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यह कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है जो हमारे देश में स्थापित होनी चाहिये। आज जो सब से बड़ी कमज़ोरी है कि अपराधी लोग हम पर हावी हो रहे हैं, अपराधी लोग राजनीति को कब्जे में कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप और हम सब इस बात के भुक्तभोगी है। अगर कोई अपराधी सलीम साहब का है तो वह अपराधी नहीं है और अगर कोई मेरे साथ है तो वह अपराधी है। यह हिसाब हो गया है आज कल इस देश के अन्दर राजनीति में। अपराधी की परिभाषा बदल गई है। अगर वह कांग्रेस का है तो अपराधी नहीं है उसके राज में और बी.जे.पी. का है वह बी.जे.पी. के राज में अपराधी नहीं है। ऐसे उदाहरण हमारे यहां आपको कम मिलेंगे, बाकी जगह ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। (**व्यवधान**)

**श्री मोहम्मद सलीम:** इस सर्टिफिकेट पर आप खुद ही सिग्नेचर कर रहे हैं (**व्यवधान**)

†श्री मोहम्मद सलीम: इस सर्टिफिकेट पर आप खुद ही सिग्नेचर कर रहे हैं (व्यवधान)

**श्री रामदास अग्रवाल:** ऐसा हो रहा है सलीम साहब। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको रोकिये। चाहे आप रोकें, चाहे मैं रोकूं, हम मिल कर रोकें। इन अपराधियों को संसद में आने से रोकना चाहिये। हमें ऐसा कहने का दुर्भाग्यपूर्ण अवसर नहीं आना चाहिये कि मेरे सामने बैठा हुआ सांसद किसी बलात्कार केस का अपराधी है, ऐसा मौका नहीं आना चाहिये कि मेरे सामने बैठा हुआ मिनिस्टर कोई हत्या का जिम्मेदार है। ऐसे मौका आने से हमें शर्म आती है, हमें लज्जा का अनुभव होता है। हम अपने सहयोगी के बारे में इस प्रकार का उच्चारण करें मुझे तो कम से कम बड़ा लज्जास्पद लगता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों के बारे में कभी संसद में गम्भीरता से विचार होना चाहिये। मेरा यह

†[ ]Transliteration in Arabic Script

प्राइवेट मैम्बर्स रेज़ोल्यूशन है लेकिन यह मेरा अपना नहीं है, मैं तो विचार रख सकता हूं। हो सकता है कुछ विचारों से मेरे सांसद बंधु पूरी तरह सहमत न हों लेकिन मेरी छोटी सी भावना है कि यदि देश का निर्माण करना है, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, देश को यदि मजबूत और स्वावलम्बी बनाना है, देश को बलवान, शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए संसद को निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ेगा वरन् इस देश की जनता सब से निपटना जानती है। हम सब से भी निपट लेगी। फिर हम न जाने कहां-कहां डोलते फिरेंगे। कोई कहां होगा, कोई कहां होगा।

हम तो आजकल ऐसी बातों में डूबे हुए हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। राजनीति ऐसी चल रही है कि अगर मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है तो मेरे प्रधान मंत्री पर कैसे न लगे। अगर मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है तो मेरे सहयोगी मंत्री कैसे बच जाएं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर इतना हल्का कीचड़ उछालते हैं महोदया कि कई बार तो लज्जा आती है। मैंने जैसे निवेदन किया था कि जब मैं संसद में आया था मुझे गौरव का अनुभव हो रहा था। लेकिन मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूं कि आखिर हम सब इतने बुद्धिमान है, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर, सी.पी.आई (एम) के अंदर इतने बुद्धिमान डाक्टर लोग हैं, युनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स लोग हैं, इतने लोग यहां पर हैं, जनता दल के अंदर बहुत कम नहीं तो बहुत सारे तो बुद्धिमान होंगे ही होंगे, उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय तो मुझे प्राप्त करना पड़ेगा लेकिन होंगे जरूर क्योंकि आखिर वह बड़ा दल है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

**एक माननीय सदस्य :** फिक्र नहीं कीजिए मिल जाएंगे।

**श्री रामदास अग्रवाल :** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमको इस देश के अंदर अपराधियों को रोकना है राजनीति में आने से, यदि हमें देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, इन कांडो को समाप्त करना है, इस देश को बलवान और शक्तिशाली बनाना है तो महोदया, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं अपने इस संकल्प के माध्यम से कि संसद यह संकल्प करे कि लोकपाल विधेयक बिल जो आए उसको एक्जास्टिव बनाया जाए ताकि ऐसा कोई व्यक्ति इससे न छूटे, इसकी पकड़ से मुक्त न हो सके। यह मेरा पहला सुझाव है महोदया। मेरा दूसरा सुझाव है कि प्रशासनिक मशीनरी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भ्रष्टाचार निरोध कानून को और भी अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि यह प्रशासनिक मशीनरी किसी भी प्रकार से उसकी पकड़ से बाहर न हो पाए। यह जरूरी होगा ताकि उन पर भी और नियंत्रण लगाया जा सके और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। यह मेरा दूसरा सुझाव है। महोदया, जो मेरा तीसरा सुझाव है वह यह है कि जो निर्णय विधायिका कर सकती है, जो निर्णय प्रशासन को करने चाहिए वे निर्णय उनको करने ही चाहिए। लोगों को कोर्टों में जाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। विधायिका को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उस पर भी कोई न कोई ऐसा अंकुश लगाया जाए कि वह निर्णय अंकुश लगाया जाए कि वह निर्णय ले और निर्णय लेने के बाद अगर कोई कोर्ट में जाए तो जाए। वह अलग बात है। लेकिन सरकारी अनिर्णयों से, इनडिसिजन के कारण जो कोर्ट में जाते हैं यह गलत है और चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री या अधिकारी है उनकी एकाऊंटेबिलिटी हो। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि उनकी एकाऊंटेबिलिटी के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए ताकि जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, उनके जाने के बाद भी पकड़ा जाता है तो उन पर भी अंकुश लगाया जा सके। यह मेरा चौथा सुझाव है। पांचवा सुझाव महोदया मेरा यह है कि सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। आज महोदया हर कोई व्यक्ति राजनीतिज्ञ बेचारे को सीधा-साधा मानता है और चाहे जो उसके ऊपर कीचड़ फेंक देता है। इसको भी कहीं पर रोकना होगा। किसी अखबार में कोई मनचाहा, बेबुनियाद आरोप लगा देते है। उस आरोप को कैसे रोका जाए इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह कम से कम प्रथम दृष्टया अगर कोई आरोप है और वह साबित होता है तब तो वह प्रकाश में आए फिर वह जनता के बीच में जाए। लेकिन केवल अनुमान के आधार पर अखबार की टेबुल पर बैठकर आरोप लगा दिए जाएं या फिर किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा राजनीतिज्ञों पर जो कीचड़ उछाला जाता है उस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई मशीनरी कायम की जाए जो प्रथम दृष्टया जो अपराध होता है या भ्रष्टाचार होता है राजनीतिज्ञों का उसके बारे में जांच कर सके और जांच होने के बाद यदि उसमें दोष है तो उसको सजा दी जाए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये पांच सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं।

मैं अंत में अपने सभी सांसद महानुभावों से और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे अंतकरण की भावनाओं को देखते हुए देश के उत्थान और देश की प्रगति के लिए, देश के नव निर्माण के लिए आप मेरे सुझावों पर विचार

करें। इतना ही निवेदन करते हुए मैं यह रिजोल्यूशन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री बनारसी दास गुप्ता** (हरियाणा) : मैं आपकी बिना इजाजत के बोलने की धृष्टता कर रहा हूं। दो शब्द कहना चाहता हूं और वे यह है कि रामदास जी अग्रवाल ने जो प्रस्ताव रखा है वह देश की आज ज्वलंत समस्या है। उन्होंने देश की दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा है। यह दलगत राजनीति की बात नहीं है। यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। मैं अग्रवाल साहब की भावनाओं की कद्र करता हूं। क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं इसलिए मैं बधाई देता हूं श्री रामदास अग्रबाल जी को जिन्होंने ऐसे संकल्प को यहां प्रस्तुत किया है जो कि आज देश की बड़ी भारी ज्वलन्त समस्या है। मैं सभी संसद् सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित करे और सब को मिलकर कोई ऐसा संकल्प करना चाहिए कि इस देश की जो स्थिति भ्रष्टाचार से बुरी हो चुकी है इसको हम ठीक कर सकें। धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : बनारसी दास जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। आपके साथ-साथ हम सभी लोग इसमें शमिल हैं कि दल से उपर उठ कर कुछ चर्चा इस विषय में होना बहुत जरूरी है।

DR. D. VENKATESHWAR RAO (Andhra Pradesh): Madan Vice-Chairperson, I rise to support the Resolution moved by Shri Ramdas Agarwal. Actually, there is a separate Resolution listed for today against my name at No.2, and the contents of my Resolution are similar to those in the Resolution moved by Shri Agarwal. So, I also share his views.

A few years back whenever we came across a scam or a corruption case, the amount involved used to be in thousands of rupees. Sometime later it used to be in lakhs and a little later in crores. Now these scams have become routine matters. They are not in one or two crores. Now a scam involves Rs 50 crores, Rs 100 crores, one or two thousand crores or more. This is the kind of atmosphere which is prevailing in the country. And at whose cost?

Very recently it was stated by somebody that to be involved in a scam has now become a status symbol. But at whose cost? Thousands of crores are being pocketed and high level people are involved, but at whose cost? Even after 49 years of Independence, it is at the cost of the po man, the poor man who cannot get a full me to fill his stomach, the poor man who cann get a shelter for himself, the poor man wh cannot get the benefits of education, health ar so on, the poor farmer whose sweat is feedir this country. It is at the cost of the poor peop that these scams are taking place.

If you go through the recent scams, you w get a lot of details. I have got a big list of scan which occurred in the recent past. Here is on for instance: "165 million bank sca unearthed." This is dated May 24. "Huge ca deposits were made in the banks of Bombay Indian rupees. Forged documents, fabricat customs clearance certificates and bills of ent were produced, showing imported roug diamonds and computer parts." "Rs. 550 cror was funnelled abroad officially through th accounts of the Hongkong and Shanghai Bank

*4.00 P.M.*

"Rs. 100 crores were siphoned off fro Calcutta banks". This is another scam. Th Allahabad Bank, the Bank of Baroda and th Punjab National Bank were involed siphoning off of these Rs. 100 crores.

Another scam was the Rs. 400 crore Ranc land scam. Morethan 100 acres of primary lar in Ranchi town was illegally transferred several individuals.

There was the molasses scam in U.P. hundred cattle-feed firms of Uttar Prades allegedly diverted their entire allotted stocl of molasses to distilleries at exorbita blackmarket rates.

Nineteen cases of medical scams are to b probed. There was the Rs. 50 crore medic scam in Delhi.

Also, there were violations by satellite T companies of the FERA regulations. Two doze TV channels are reportedly paying millions dollars towards transponders' rental to foreig companies in hard currency.

There is the Nadia scam. This is a land scar

So many scams are of recent origin. W know other areas where scams have taken plac For example, there is the recent Rs. 133 cror urea scam. At whose cost? During that perio

the poor farmer was running around for urea. He purchased it in the blackmarket. But Rs. 133 crores were sent away from our country without the RBI permission by involving the political as well as the official machineries.

There is the animal husbandry scam in Bihar. This is also in front of us.

The other scams are: There was the Rs. 5,000 odd crores bank scam in which the hard earnings of so many poor and middle classes put in banks were involed.

In these areas, the JPC was constituted. The JPC gave some recommendations. After that, the Action Taken Report was given. Even then, the culprits were not caught. Lakhs and lakhs of small people, poor and middle class people were affected. Their hard-earned money was lost.

Coming to other scams, regarding the Hawala Scam,we all know very well that in 1991 the CBI found the Jain diary while raiding the Jain houses, but in 1994 some third party filed a petition, and the CBI was asked to produce the Jain diary before the Supreme Court. At that time many people were involved in it.

We all know how exactly these scams were going on.

In the same manner, if we come to other Departments, for example, the Railways, we all know that in 1994 the Consultative Committee and other committees of the Railway Department opposed the purchase of 5,000-HP engines from foreign companies like the ABB etc. Even then, the Government at that time refused to accept the recommendations of these committees, and it went on purchasing railway engines and railway wagons at higher prices. If the normal price was Rs. 5,000, it purchased it for Rs. 10,000 to Rs. 15,000.

Likewise, there have been so many other scams. They have been there everywhere, in every department. We are seeing that petroleum and petroleum product consumption has been increasing day by day. At present we require one million gallons of petroleum and crude petroleum products every day. Previously the country's requirement was less than this. At that time we imported 40 per cent of our requirement. Now we are importing 50 per cent of our present requirement. By the end of the century, we will be consuming two million gallons of petroleum products every day. What would be our import requirement at that time? At present we are spending 30-40 thousand crores of rupees in foreign exchange to purchase the crude and oil products. Now we have increased the price of these products at the cost of the poor man who has been suffering since long. The ONGC and other connected departments are not taking care of the real situation that is obtaining in the country. Nor do they have any plans about the availability of oil and oil products wealth in the country. They could not explore them properly. They are working just for the sake of a few individuals who are exploiting the whole wealth of the country for their own benefit.

In the same manner we know how much power generation is needed. We also know how private parties are coming and quoting their prices for setting up power projects. For example, while the State Electricity Boards are constructing power projects at a cost of Rs. 2/- crores per mega watt of power, private parties are quoting Rs. 4/- crores to Rs. 5/- crores per mega watt. For example, the Vizag-Hinduja Project, the Dabhol Project, the Cogentrix Project, which I have come across, are having their power purchase agreements, which are much higher.

Similarly, we know very well about the sugar scam.In 1994, there was shortage of sugar. The Cabinet was informed about it in time, but no arrangements were made to import the sugar in time. On the other hand, the black-marketeers were informed about the situation. They started importing it. The original cost was about 190 dollars per tonne. It had been increased to 350 to 400 dollars per tonne. Rs. 2,000 crores of the country's money was spent in this way. This is how the normal price of sugar, which used to be Rs. 10 per kg. had gone up to Rs. 16 per kg. In the process the poor man suffered.

So,all these types of scams are there around us. They are at the cost of the poor man, who has been suffering for the last 49 years, who could not get a full meal to fill his stomach, who could not get education and proper health

facility. It was at their cost that Rs. 3,000 crores were squandered away.

In this situation it is our duty to evolve a concrete mechanism so that those who are in high offices and are involved in this kind of scams are booked. The Lok Pal Bill is being contemplated by the present Government and is being talked by every party. When we are thinking of this kind of a Bill, let us be very cautious also. Already Lok Ayukta is there in the States, but it has not been of any help so far. This is our practical experience. Lok Ayukta goes into allegations and scams and all that, but it could not do anything, because its report is scrutinised by its appointing authority i.e., the Cabinet. It is the Cabinet, which has to take a decision. If this kind of an arrangement is there in the case of Lok Pal also, then it will also not be of any help.

So, in this case an autonomous body has to be constituted. It should be directly under the control of the President. It should go into every aspect of the scam, every aspect of corruption that is taking place in the country. It should be responsible to the highest authority. It should not be influenced by anybody.If you constitute a body or a commission, it would be of some use and then there would be some respect for the politicians in the country. With these, I conclude, Madam. Thank you.

**श्री मूलचन्द मीणा** (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, श्री रामदास अग्रवाल जी जिस भावना से गैर सरकारी संकल्प लाए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वह एक अच्छा संकल्प है और आज के समय के अनुसार इसकी बहुत आवश्यकता है। मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन दिवानों ने अपने आपको न्यौछावर किया, जिन लोगों ने देश को दुर्दशा से, परतंत्रता से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, उन लोगों की भावना नहीं थी कि आजादी के 50 साल बाद हमारे देश के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा, हमारे लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने वाला समय आएगा। महोदया, आज इस भ्रष्टाचार से लाकेतंत्र को खतरा हो रहा है। चाहे हम विधायी संस्था को लें, चाहे कार्यपालिका को लें, चाहे न्यायपालिका को लें, हमें चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। चारों और बगैर पैसे के, रिश्वत के काम चलता ही नहीं है। न्यायालयों की स्थिति तो और भी दयनीय है। छोटे न्यायालय से लेकर बड़े न्यायालय तक देखिए, तारीख-पेशी चेंज कराने के 10-10, 20-20 रुपए बगल में बैठा बाबू लेता रहता है, जज और मुंसिफ देखते रहते हैं। यह तो प्रत्यक्ष रूप है। आज कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंदर बैठे हुए लोग भी इस भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। जहां जिसका दाव लग रहा है, चाहे वह छोटा प्रशासक हो या बड़ा प्रशासक हो, वह अपना दाव लगा रहा है। देश की सेवा करना, शासक व्यवस्था में अच्छे सेवक के रूप में शासक पैदा करना, यह ध्येय था आजादी के दीवानों का, यह उनकी भावना थी। आज जिस प्रकार का वातावरण देश में बना हुआ है, यह उनकी भावना नहीं थी। क्या कारण है कि आज जो कुर्सी पर बैठ जाता है, चाहे मंत्री बनने के बाद, चाहे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, चाहे प्रधान मंत्री बनने के बाद, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? देश का शासन जवाहर लाल नेहरू ने भी किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, इंदिरा गांधी ने भी किया, राजीव गांधी ने भी किया। लेकिन राजीव गांधी से शासन छीनने के लिए लोगों ने उस साफ-सुथरे आदमी पर आरोप लगा दिया। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा-वी.पी. सिंह जी जयपुर के अंदर गए थे, वहां बहुत बड़ा रामनिवास गार्डन है, जिसमें पब्लिक मीटिंग हुई थी और वी.पी. सिंह ने एक बात कही थी कि आप राजीव गांधी को हरा दो क्योंकि राजीव गांधी ने बोफोर्स में पैसा खाया है। यदि आपने हरा दिया तो राजीव गांधी को एक महीने के अंदर जेल भेज दूंगा। वोट की खातिर हमने अपनी नैतिकता को भी खो दिया, झूठ बोला पब्लिक में। लोगों ने राजीव गांधी को हरा दिया, वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री बने, लेकिन राजीव गांधी को कहीं आज भी दोषी नहीं पाया गया। आज किसी दल के लोग हों, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सब अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं, अपने ईमान को बेच सकते हैं, नैतिकता को खो सकते हैं, नैतिकता नाम की कहीं चीज नहीं है। अग्रवाल जी जब बात कर रहे थे नैतिकता की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यह पिछले जो चुनाव हुए और उसके बाद जो संसद बनी तो उसमें नैतिकता नाम की कहीं चीज ही नहीं है।

देश के अंदर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। गठजोड़ करके इनके 194 सदस्य थे और अटल बिहारी वाजपेयी के 161 सदस्य थे। वे 60 सालों से राजनीति कर रहे है। एक महीने तक इतने बड़े मुल्क में किसी पार्टी का शासन नहीं रहा। आपने बाद में शासन की बागडोर संभाली और आप नैतिकता की बात करने लगे। फिर संसद में आकर वाजपेयी जी बहुमत नहीं जुटा पाए। बहुमत जुटाते कहां से? आपके पास बहुमत था ही नहीं। आपके अंदर नैतिकता होती तो आप शपथ ही नहीं लेते।

महोदया, इस सदन को, दूसरे सदन को, सारे देश को और पोलिटिशियंस को यह सोचना पड़ेगा कि जिन नैतिक मूल्यों के ऊपर यह प्रजातंत्र, यह लोकतंत्र टिका हुआ है, उन मूल्यों को वापस लागू किया जाए, सबको उन मूल्यों पर चलना पड़ेगा। आज कार्यपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है। न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं और वह अपनी सीमाओं को लांघकर काम कर रही है।

महोदया, मुझे आपके समक्ष यह बात कहनी है कि संसद सदस्यों के मकानों का संबंध केवल संसद सदस्यों से होता है। वहां कोई दूसरा नहीं रह सकता लेकिन आज न्यायालय में इस पर भी जन-याचिका लग गई है और जज लोग सुन रहे हैं। यह अफसोस की बात है। आज न्यायपालिका में बैठे हुए कुछ लोग भी करप्शन में लिप्त है। प्रशासन के अंदर बैठे हुए लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है। आज इन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. आफिसर्स की बात ले लीजिए। इनको प्रति माह 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती होगी लेकिन इनके परिवार का खर्च 20-25 हजार रुपए प्रति माह होगा। उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे सबसे अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे। उनकी औरतें क्या करेंगी? वे अच्छे ब्यूटी-पार्लर में जाएंगी, अच्छे होटलों में खाना खाएंगी। यह पैसा कहां से आया? आज प्रत्येक आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी की संपत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह संपत्ति कहां से आई?

अगर छापे मारे जाएंगे तो किन लोगों के घर मारे जाएंगे? जो सबसे करप्ट लोग हैं, उनके घर छापे नहीं पड़ेंगे। कोई एस.सी. या एस.टी. का आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारी होगा, जिसकी आगे तक पहुंच नहीं होगी, उसके घर में छापा पड़ेगा। भ्रष्ट कर्मचारियों के घर में तो छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वे तो हिले-मिले रहते हैं उन लोगों से जो छापा डालते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ छापा कौन डालता है? पुलिस के अधिकारी ही छापा डालते हैं चाहे वह जांच सी.बी.आई. के अंतर्गत हो या सी.आई.डी. के अंतर्गत हो। वे भी तो लिप्त हैं इस करप्शन में। आज आप सी.बी.आई. के अधिकारियों की संपत्ति की जांच करा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वे भी इस करप्शन में लिप्त हैं।

महोदया, इस देश की आजादी के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी भावना को जीवित रखना होगा। आज भ्रष्टाचार ने घोटालों ने, कई प्रकार की नीतियों ने और अनैतिक कार्यों ने उस भावना का रूप खराब कर दिया है। उसको ठीक करने के लिए सभी दलों को मिलकर एक आचार-संहिता बनानी पड़ेगी, एक रास्ता बनाना पड़ेगा तब जाकर हम सही मायनों में लोकतंत्र को कायम रख सकेंगे। अन्यथा हमारे लोकतंत्र को खतरा बना रहेगा। महोदया, कई बार बात केन्द्र में हुए घोटालों की होती है। अग्रवाल जी तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं।

राजस्थान के अंदर तो यह कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं। मैं अग्रवाल जी से यह ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां पार्टी की चीफ हैं। आपकी जो सरकार कर रही है, आपके मुख्य मंत्री जी जो कर रहे हैं, उन घोटालों से जरा राजस्थान की जनता को छुटकारा दिलाएं। हम आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं। आप जो कदम बढ़ाएंगे उसमें साथ रहेंगे। वहां एम. फोर्ड कम्पनी में चीफ मिनिस्टर के भाई डायरेक्टर हैं जिसमें जनता का दो सौ करोड़ रुपया इकट्ठा करके खा गए, कुछ पता ही नहीं चला। एम. फोर्ड एक प्राईवेट कम्पनी बनाई थी। उसमें दो सौ करोड़ रुपए का पता ही नहीं चला।

**श्री रामदास अग्रवाल:** महोदया, मुझे अगर इजाजत दें तो कुछ कहना चाहता हूं।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** अब अगर आपको इजाजत दूं तो उनका भी बढ़ जाएगा, फिर बाकी लोगों का टाईम कम करना पड़ेगा।

**श्री रामदास अग्रवाल:** केवल एक मिनट। माननीय सदस्य ने कोई एम. फोर्ड कम्पनी घोटाले की चर्चा की है। यह राज्य सरकार का विषय है। उसकी जांच भी हो चुकी है, अपराधी जेल में हैं और मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस मामले को लेकर के इनकी पार्टी ने छः महीने त क धरना भी रखा, उसके बाद स्वयं उठा लिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों उठा लिया।

**श्री मूलचन्द मीणा:** मैं आपको तथ्यों के आधार पर बतला रहा हूं। एम. फोर्ड घोटाले में भैरो सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई थे।

**श्री रामदास अग्रवाल:** किसी का नाम लेकर यहां उसकी चर्चा करना मेरे ख्याल में उचित नहीं है। मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं नहीं। मैंने अपने पूरे भाषण में कहीं किसी का नाम नहीं लिया। मैं स्ट्रांगली अपाज करूंगा इस बात के लिए।

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY**

OF PARLIAMENTARY AFFARIS (SHRI S.R. BALASUBRAMNIYAN) : You said so many things about Scams. *(Interruptions)* You referred to so many Scams. *(Interruptions)*

SHRI RAMDAS AGARWAL : During my forty-five mintues speech, I have not named anybody. *(Interruptions)*

SHRI S.R. BALASUBRAMANIAN : Now, let him have his say. Don't interrupt him. *(Interruptions)*

SHRI RAMDAS AGARWAL : I am not interrupting. I am saying... *(Interruptions)* Otherwise, he can say whatever he likes.

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) :** मीणा जी, मुझे लगता है कि इसमें किसी मंत्री का नाम नहीं लें। बहुत ज्यादा विवाद खड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। आप अगर बगैर नाम लिए बोलना चाहें तो जरूर बोलिए, आपका वैसे भी समय हो चुका है। मेरे सामने वक्ताओं की लम्बी लिस्ट है। मुझे फिर आपके लिए कहना पड़ेगा कि आप बाइड अप कीजिए।

**श्री मुलचन्द मीणा:** मैडम् गंभीर सब्जेक्ट है। मैं अग्रवाल जी की बात से सहमत हूं। मैं अग्रवाल जी से कह रहा हूं कि हमने छः महीना धरना दिया कि इसकी सी.बी.आई. से जांच कराई जाए। मुख्य मंत्री जी तैयार नहीं हुए क्योंकि उनका सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए वहां कांग्रेस के कार्यकर्त्ता धरने पर बैठे रहे। वहां जो जजों की नियुक्त हुई। आर.एस.एस. के कुछ सदस्य रह कर जज बन जाते है। वह फैसला भी उसी भावना से करते हैं, न्यायायिक भावना से नहीं करते है। इस प्रकार की रिट लगाई गई थी कि सी.बी.आई. से जांच कराई जाए। उस रिट पर वहां के जजों ने इजाजत नहीं दी कि सी.बी.आई. से जांच हो। बिहार के अंदर जो चारे का घोटाला था उसमें हाई कोर्ट के जजों ने यह इजाजत दी कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए, क्योंकि वहां निष्पक्ष जज थे। लेकिन वहां जज भी उन भावनाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए कैसे माना जाए कि आगे चलकर देश में प्रजातंत्र कायम रह सकेगा। अग्रवाल जी ने लोकपाल बिल की बात कहीं। लोकपाल की स्थापना का बिल यह सरकार इस सदन में ला रही है। लोकपाल की स्थापना के बाद क्या यह मान लिया जाए कि यह सारा भ्रष्टाचार मिट जाएगा। यह असंभव बात है। आज राजनीतिज्ञ नेताओं की स्थिति यह है कि वह जब निकलते हैं तो लोग कहते हैं यह आ रहे हैं-चोर, करप्ट भ्रष्ट हैं। ऐसी भावना लोगों की इन राजनीतिक नेताओं के प्रति हो गई। जबकि राजनीतिक नेता इतना अपराध, इतना पाप नहीं करते हैं लेकिन इस प्रकार बदनाम कर दिया गया है। यह नैतिकता की बात करते हैं मैडम्, अयोध्या का क्या झगड़ा है। वोटों की खातिर ह लोगों को बहका सकते हैं, लोगों को आग में झौंक सक हैं, लोगों को मार सकते हैं, लोगों को मरवा सकते हैं, दं फैला सकते हैं। यह सब नैतिकता की बात तो तब आ इन सारी बातों को हमें छोड़ना होगा, हमें अपने स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और नैतिक मूल्यों को धारण करना पड़े तब जाकर अग्रवाल जी, जो संकल्प लाए हैं वह साक हो पाएगा। अग्रवाल जी, आगे चलें, उनके साथ हम चलें। लेकिन नैतिकता के पाठ को पहले अपने लोगों पढ़ाएं उसके बाद हम आपके साथ है। साथ ही प्रशास के अधिकारियों का एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा उस प्रशासन को कैसे दूषित कर दिया है इन लोगों ने, इन सांसदों से संबंधित है। प्रोटोकाल की लिस्ट में सा केबिनेट सेकेटरी से उपर है मगर आज क्या स्थिति एम. पीज़ को रहने के लिए बंगला, साउथ ऐवेन्यू, न ऐवेन्यू या "सिक्स टाइप" का बंगला मिलेगा, सुविधा मिलेगी और उससे कम जो नीचे प्रोटोकाल हैं, "ऐट टाइप" बंगले में रहने के अधिकारी है। कैसे सिस्ट बना यह? किसने बिगाड़ा इस सिस्टम को? कहां है सिस्ट जो प्रोटोकाल में उपर है उसको उतनी सुविधाएं हो चाहिए थीं रहने की लेकिन उन सबको चेंज कर दिया अधिकारियों ने मिलकर, कुछ स्वार्थी लीडरों, नेताओं मिलकर इस सारे प्रोटोकाल सिस्टम को खराब किया जो प्रोटोकाल में उपर है वह तो कम टाइप के मकान रहेगा, छोटे मकान में रहेगा और जो प्रोटोकाल में नीचे वह हाई टाइप के मकान में रहेगा, कोठियों में रहेगा, कौन सा सिस्टम है? इसीलिए अग्रवाल जी जिस भाव से यह बिल लाए हैं, सारा सदन एकमत हो कर और दू सदन के लोग भी इस बात से राज़ी होंगे कि आज देश लोकतंत्र को बचाने के लिए नैतिकता को ग्रहण व लोकतंत्र के मूल्यों को ग्रहण करें, लोकतंत्र में आई खराबियों को दूर करने के लिए पार्टी के सिद्धान्तों छोड़ कर पार्टी एक तरफ रहे, देश का लोकतंत्र एक त रहे, इस पर आएं और इसी बात को लेकर हम इस संक को पास करें कि आने वाले भविष्य में लोकतंत्र की के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की मजबूती के लि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए (व्यवधान)...

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) :** मीणा जी, क कीजिए। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है वक्ताओं की, क्या करूं? समय की पाबन्दी तो सभी के उपर हो चाहिए?

**श्री मूलचन्द मीणा:** मैं खत्म ही तो करने जा रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** खत्म कीजिए। आप बहुत लम्बा मत बोलिएगा।

**श्री मूलचन्द मीणा:** देश की मजबूती के लिए इस संकल्प के लिए बिल लाया जाए और पास किया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** श्री सनातन बेसि। देखिए समय का ध्यान आप भी रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और बोलने वाले लोग काफी हैं।

SHRI SANATAN BISI: Madam, I am quite aware of it. I won't take much time.

Madam, this is really a very solemn occasion when we are discussing the menace of corruption. So far as the present Bill is concerned, whether it is this side or that side, we should be united and we should sincerely try to know the causes of corruption. Now I would like to submit one thing. So far as this House is concerned, so far as the other House is concerned and so far as the people, at large, are concerned, Madam, you will be happy to know that the United Front Government and our Prime Minister are striving a lot to review the whole system in such a manner that there shall be no corruption in our society. As you know, we are going to introduce several Bills, and so far as those Bills are concerned—several Members have also stated this—primarily I would like to say one or two things. The United Front Government is committed for the Lok Pal Bill, for the review of the Official Secrets Act. And as you know, so far as the discretionary quota is concerned—as it was prevailing, and there are chances of corruption—already the Ministers have been instructed in this regard. Our Governmnt is committed to bringing in electoral reforms as well as reforms in the judicial system. Sometimes in the House as well as outside the House when we talk of morality and of the men which is popularly known as "Mulyabodha" for upholding moral values, we very often take the name of Shri Lal Bahadur Shastri, and whenevr some occurrences take place and we talk about those moral values, at that time with all solemnity we take the name of late Shri Lal Bahadur Shastri and I would like to put on record some of things which Shri lal Bahadur Shastri said. There was a debate in Parliament on 9th June, 1962, Shri Lal Bahadur Shastri—he was a Home Minister at that time—taking into account the growing menace of corruption appointed a Committee. That Committee was known as the K. Santhanam Commitee—Mr. Santhanam was a Member of Parliament—and that Committee submitted its Report on 30th March, 1964; that Committee had considered, at great length, all the aspects and had reviewed the circumstances, the circumstances which were prevailing in the year 1964 as well as the circumstances prevalent prior to that period.

That Committee had at length examined the nature of the problems, the extent of corruption, conduct rules, disciplinary rules, preventive measures and the law and order situation relating to corruption. I would like to submit before the House, Madam, that after the submission of the Report by the K. Santhanam Committee in the year 1964 nothing has been done. It is very clear that the Governments at the Centre led by various political parties had never cared to implement the recommendations made by the Committee headed by Shri K. Santhanam, Member of Parliament. If those recommendations had been implemented properly, our society would have been clean. Another point which I would like to submit, as my learned friends have already stated, is that we are all aware of the fact that there is corruption in all walks of life. The moral values of our society have gone down too low. When provisions like section 161 of the Indian Penal Code, section 5(1) of the Prevention of Corruption Act, 1947 and section 123 of the Representation of the People Act, 1951 are there, offences are being committed and the punishment is being meted out very rarely. It is because our society, our whole system, is degraded to such an extent that we do not care for all these provisions and procedures.

As you know, Madam, it is under the leadership of Mahatma Gandhi, who is known for his personality, integrity, honesty and non-violence, that we fought for the freedom of our country and we got it. Unless and until the legislators and politicians at all levels are clean,

we cannot administer the society in a proper manner and do justice to the people.

Another point which I would like to submit is regarding judicial activism. Why did judicial activism come to the force? People really think that judicial activism would give them some result. It is because of the political instability and political inconsistency that is prevailing. I am not going to name any Government. It was solemnly agreed that we would discuss all the aspects and bring to the limelight that we were above politics. Whatever we are discussing today is for the good of the society. So far as the question of cleaning the society is concerned, our Government is committed. I hope that our Government will take steps accordingly. As far as the Report submitted by the Santhanam Committee is concerned, I would submit that it should be acted upon. With these words I conclude and thank you for giving me this opportunity.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam Vice-Chairperson, I would like to thank Ramdas Agarwalji for bringing this Resolution on a point which, I think, agitates the minds of not only the Members of this House but also the people of the entire nation. In fact, in the recent past all of us had taken part in an election process. I think, among many other issues, the types of issues which have been sought to be raised in the Resolution have been agitating the minds of the people. Now the first point that I would like to make here is that it is true that one really need not go anywhere, if one is to judge the issue from a partisan angle. But at the same time, what is really corruption? The ways for rooting out corruption can be formulated only if we can really define and we can really determine the factors which go into the very notion of corruption. I think corruption is not a subjective activity. The House has to be disabused of the fact that it is an aberration. I think corruption is a product of a specific socio-economic and political reality.

The point we are discussing here today is corruption is increasing. Corruption is in a process of genesis that has been recognised in the Resolution itself. But how, in the first place, corruption came into being! As long as there were no divisions in the society, there were no surpluses to be appropriated, there was no objective basis for the emergence of corruption As and when the notion of individual property developed, the notion of corruption came into being. So it is an age-old notion. But what today distinguishes the issue of corruption, as never in the past, is the frightening dimension that it has corruption and the implications with which that corruption has come to be associated, in my opinion, not only threaten democracy but the very existence of we Indians as people and the nation. So here lies the importance of the issue that it has assumed today at this point of time. Now I don't want to go back to the days of that kind of primitive society. But in a more contemporary Indian context, what are the political factors that have gone into the real frightening dimension of corruption as we have seen today? I think one of the major factors is, politics which was a propelling factor for the future movement of the society, of human activities, has taken a back seat. We are quoting certain individuals, certain personalities, who played a unique role in our freedom struggle. At that point of time a certain principle, idealism, was followed by millions of people for a cause. Now we have seen, over a period of time, a systematic effort at idolisation of people. Really, that is why we have to search for an answer. Unless there are certain principles, unless there are certain ideals, on the basis of which people can be united—it can be a political issue, it can be a social issue or it can be some other issue—there have to be certain ideals which will spell unity of the people, it is on the basis of the elevated level of popular awareness that corruption can be fought out. I think we can discuss corruption for any length of tie. But ultimately the system cannot develop any loophole-free safeguard for itself for cleansing social processes, political processes unless there is a sufficient awareness among the people against all these things. The requisite level of awareness of the people can only come about if we put forward certain ideals which people will embrace and on the basis of which the imagination of the people will be fired. It is in this context that I would also like to move a small amendment to the original Resolution. I think not only corruption but communal and sectarian understanding should be added in the first line itself because these things are becoming interconnected. Mr. Meena

was also trying to say it. Actually, what is corruption? Apart from economic offences, if I try to evoke certain religious sentiments of the people to ask for votes, it is as much condemnable as somebody committing economic offences to really assert political power.

Therefore, I feel, that this issue should also be taken into account. It is also connected with the question of democracy. We have a democratic system. We have a political system. We have a Constitution. Now this kind of things, corruption and communalism, make us operate beyond the confines of democracy and the Constitutional scheme of things. As a result of this, we are having the kind of changes that are taking place in the economy.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS. SAROJ KHAPARDE): Mr. Basu, kindly conclude.

SHRI NILOTPAL BASU: I will take another three to four minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS. SAROJ KHAPARDE): I will have to then cut down three to four minutes from some other Member's time.

SHRI NILOTPAL BASU: I can conclude right now if you want me to.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS. SAROJ KHAPARDE): Mr. Basu, please don't misunderstand the Chair. I am not asking you to conclude right now.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Let him speak, Madam. He is talking a lot of sense today.

SHRI NILOTPAL BASU: I think, Mr. Singla does not listen to me often, otherwise, the qualification 'today' would not have been there. Anyway, as a result of this, what we are seeing today is a chilling reality and it has come out in the Vohra Committee report. Now, when I speak about these things, Mr. Singla will say, here is a communist speaking with the 18th century mind-set. The vicissitudes of the market forces as part of the reform process that we have been seeing in the last five years are directly responsible for the kind of economic offences that have been taking place. All economic offences can be directly connected to the manner in which mindless economic reforms were adopted. Dr. Rao was talking about all these things. Is it really a coincidence that the system was trying to respond to a certain economic philosophy which resulted in the committing of economic offences? These things have to be accounted for. There is a nexus between the politicians, the bureaucrats and the criminals. They run a parallel administration. I was seeing a cartoon somewhere. In the cartoon, a gentleman asks a criminal, "Is that political party protecting you?" The criminal replies, "No, we are protecting the political party. We do not need anybody's protection." This is a sad commentary on our times. Now the point is what is the way out? Mr. Bisi was talking of judicial activism. But this cannot be a lasting solution. We have the executive. We have the bureaucracy. We have the judiciary. All these have a role to play. If the executive consciously abdicates its responsibility, if there is a conscious attempt to bypass the legislature. then, the load of the system, the load of the Constitution will fall upon the judiciary and it will be forced to delve into matters which it is not supposed to. Notwithstanding some good judgements, this cannot be a healthy development for the future of our democratic system.

Therefore, some reworking of the constitutional schemes has to be done. There should be certain inbuilt constitutional devices. It is one thing to talk of ethical standards. But what can Agarwalji do? Some 70-year old Minister was beaten up by his own partymen and he was stripped in front of his leader. Even though Agarwalji brings in this kind of a resolution before the House, yet he cannot stop these things. So, the point is to institutionalise certain changes, changes to really arrest and to really eliminate certain tendencies. Therefore, what we really need is an interconnected reform process in the political and social spheres. Now, why I feel that this is incumbent upon us is I, as a Communist, feel that the people at large are thinking that the politicians of our times are failing to discharge the historical responsibility that is given to them. It is not a question of finding one man alone because the times have changed. In Science, you cannot have one single neutron or one single Einstein. So also in politics, you cannot have an individual, a outstanding leader. It has to be a collective

process. Now the realm of knowledge is so widened. It is only when we collectively put our minds to evolve a kind of inbuilt safeguards in the process itself, only when we have certain changes in the Constitution and have thoroughgoing reforms which will embrace all the areas of human existence, of national existence, that we can make a meaningful break with the kind of situation that we are faced with. Therefore, I think that that kind of a process has to start. Things like Lok Pal Bill can be a very good beginning. But I think that every day we will have to work towards devising new corrective methods to strengthen transparency, to strengthen accountability, to strengthen the democratic process and to encourage an atmosphere of meaningful debates, discussions and intercourses. It is only through our efforts and application of our collective intellect that we can really move forward. With these words, Madam, I conclude.

**श्री नागेन्द्र नाथ ओझा** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, पहली बात तो यह कि अग्रवाल जी का जो ओरिजिनल रिजोल्यूशन था उसमें इन्होंने संशोधन करके पेश किया, आपकी इजाजत से ही पेश किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा कंक्रीट मुद्दे उठाए जाते यदि उनका पहला ही रिजोल्यूशन होता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आखिर उसमें उन्होंने कहा था कि 5-6 वर्षों के अंदर करप्शन में वृद्धि हुई है। घोटाले की बात, कुछ कंक्रीट बात की तरफ इशारा था जिसके बारे में हम कुछ कंक्रीट बाते कर सकते थे। बड़ी जल्दी में हम लोगों ने इजाजत दे दी। लेकिन मैं बाद में भी जानना चाहूंगा अग्रवाल जी से कि आखिर क्या बीच में बात हो गयी कि एक ही वाक्य में रिजोल्यूशन हो गया। क्या विचार करके उन्होंने ऐसा किया। मैं कोई यह नहीं कहने जा रहा हूं कि यह भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। हम ही लोगों ने इजाजत दी। लेकिन हम समझते हैं कि जो पहली प्रतिक्रिया से पहला जो भाव आया इनके दिल में शायद ऐसा रिजोल्यूशन लाने का, उसमें वह ज्यादा अच्छे काम की कंक्रीट बात कर सकते थे। कुछ लोगों पर 4-5 वर्षों के दौरान जो घोटाले के आरोप आए हैं अधिक से अधिक उनके नाम आते यदि पहली उनकी बात होती।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** ओझा साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूं। ...(व्यवधान) प्लीज, सुनिए ...(व्यवधान) पहले जरा चेअर को भी कुछ सुनेंगे आप। आपने पहले ही अपने विचारों को रखते हुए कहा कि आप ही की अनुमति से, यहां किसी की अनुमति का कोई सवाल नहीं था, वह अग्रवाल साहब ने ही जो किया, वह किया। हमारा कोई रोल उसमें नहीं था। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कहीं आपके दिमाग में कोई परेशानी या कोई ऐसा शक न हो।

**श्री नागेन्द्र नाथ ओझा:** वैसा नहीं। चूंकि यह मामला इतना व्यापक है, पूरे देश में चर्चित है और यह नीचे से उपर तक है कि कोई अंग बाकी नहीं है। मैं भी जो भावना उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त की उसके साथ हूं और जो कुछ हुआ इस बीच में उसको मैं कोई अलग-थलग बात नहीं समझता हूं। इस तरफ इशारा करना जरूरी था। ... (व्यवधान)

**श्री सुरिन्द्र कुमार सिंगला:** सिर्फ पांच साल की ही करप्शन है, पहले बिल्कुल नहीं थी?...(व्यवधान)

**श्री नागेन्द्र नाथ ओझा:** इसके निवारण के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं, माननीय सांसदों ने जो सुझाए हैं मैं उन सुझावों के साथ हूं। यह मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे वह आर्थिक अपराध या किसी दूसरे किस्म के हमारे देश में जो कानून है वह काफी है, अगर उन कानूनों को लागू किया गया होता, हमारे देश के अंदर तो हमारी स्थिति बिगड़ती नहीं और फिर लोकपाल बिल बना दीजिए, कितना ही कानून का जंगल दे दीजिए, हमारे देश को उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। बात यहां आती है आज गांवों में और लोगों के बीच में चर्चा है कि जिन पर सब से ज्यादा भरोसा होता है कि कानून को लागू करेंगे, कानून बनायेंगे, देश की देखभाल करेंगे, राष्ट्र की चिंता करेंगे वह सर्वोच्च संस्था यहां है और उसके एक हाउस में हम लोग बैठे हुए हैं। यानी सब से ज्यादा उंगली 5-6 वर्षों के दौरान अगर उठाई जा रही है तो वह राज़नीतिज्ञों पर उठाई जा रही है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि लोकपाल बिल से कुछ काम तो बनेगा। लेकिन सत्ता के उच्च पद पर चाहे वह राजनीतिज्ञ हों या हमारे प्रशासक हों, उनको सहज ढंग से पकड़ में लाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अलग से कानून बनाने चाहिए। जो हमारे दूसरे कानूनों को लागू करने में पिछले दिनों कठिनाइयां हुई हैं उसको देखते हुए कुछ नए कानूनी उपाय किए जाने चाहिएं। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि हम सभी यहां राजनीतिक दलों के लोग हैं और यह हम पर खुद जवाबदेही आती है, वह किसी कानून से नहीं होगा हालांकि उसके लिए भी कानून है। हम अगर सामूहिक रूप से चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिएं तो हमें अपनी-अपनी पार्टियों के अंदर भी ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि

अपराधियों का प्रवेश उसमें रोका जा सके, पनपते हुए भ्रष्टाचार को वहां से खत्म किया जा सके, उसे रोका जा सके, वह कोई जड़ भी न जमा सकें। कोई विगत 5-6 वर्षों में जिन राजनीतिज्ञों पर उंगली उठाई गई है वह किसी न किसी राजनीतिक दल के ही हैं और अग्रवाल जी के कहने से यह बात यहां समाप्त नहीं हो जाती कि कोर्ट में प्रूव हो जाने पर ही किसी पर उंगली उठाई जाए, कि अगर अखबार वाले लिख देते हैं तो उसी को लेकर हल्ला-गुल्ला नहीं किया जाए। पर वह किस तरफ इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाहते थे, मैं समझ सकता था। इसलिए मेरा एक निवेदन यह है कि राजनीतिक दलों को भी अपने अन्दर उपाय करने चाहिएं।

मेरा तीसरा सुझाव होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देनी शुरू होती है वहां से शिक्षा के ऐसे प्रबन्ध किए जाने चाहिएं ताकि आगामी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी सही शिक्षा पा सके। हमारे ईमानदार नेताओं के बारे में वह पढ़ सके। आज हमारे बच्चों के कोर्सेस में उस तरह के पाठ का बहुत अभाव देखा जा रहा है।

हमें बुनियादी तौर पर इस समस्या को लेना होगा और एक-दूसरे से शिकवा-शिकायत से सचमुच में काम चलने वाला नहीं है।

महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी लोकतंत्र पर आशा रह गयी है क्योंकि जिन-जिन दलों पर शक-शुबा रहा पिछले वर्षों में, पिछले 20 वर्षों के दौरान जनता ने इसी लोकतंत्र का इस्तेमाल कर के उन्हें अपनी कोर्ट में दंडित किया, जो एक दिन के लिए मतदान की कोर्ट उस की बैठती है, उस में दंडित किया है। महोदया, अग्रवाल जी की चिंता सही है कि लोकतंत्र पर खतरा है। लोकतंत्र पर यह उंगली उठ रही है और सचमुच में इसे बचाने की यही एक दिशा बची है। महोदया, हमारे देश ने बहुत आशा की थी कि हम भारत को दुनिया के दूसरे देशों से आगे ले जाएंगे, हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं होगा और सब को समान अधिकार होगा, लेकिन-

"हसरतें सब मिट चुकीं, बाकी रहा है इक निशां,
इस को जलने दे "चिराग", उजड़े हुए मंजिल का है।"

धन्यवाद।

SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR (ASSAM): Madam, while supporting the Resolution moved by hon. Member Shri Satish Agarwal, I beg to submit that corruption has spread to all walks of life involving not only politicians and bureaucrats at higher level but also those at the lowest level of all aspects of life, making corruption a way of life itself. It has not only damaged the basic structure of democracy, but has also made all laws irrelevant. There is no rule of law. There is no accountability on the part of anybody either in the Government or in other departments governing the affairs of human life.

In my State, Assam, Government jobs were being sold in auction openly. The malady spread to the Public Service Commission which is a Constitutional body. There is no question of any merit in selection of candidates for jobs. The person who pays the highest gets it. In a poor State like Assam, Rs. 200 crores were looted from one Government Department that is, the Veterinary Department of the Government of Assam. Inquires have revealed involvement of bureaucrats, politicians and Government servants from the highest to the lowest level. An inquiry by another responsible Government officer has revealed that there are such scams in twelve other departments of the Government of Assam. But curiously enough, no inquiry is being conducted to find out the extent of the amount looted an the persons who are involved in those scams.

Such scams involving looting of public money are there not only in Assam but in all the other States of India. There are the C.I.D., the Anti-Corruption and other departments dealing with corruption but no action is being taken by them to bring the culprits to book.

Lumpen elements have taken over most political parties and Even Governments. These elements have no connection with the ethos and the high ideals that led the Indian people to make sureme sacrifices and undergo sufferings in the movement for attainment of freedom. And, I am proud that I was a participant in that movement and had to suffer much during the freedom movement. There is no check by political parties to prevent criminals from entery into politics and being elected as representatives of the people. The stories of politicians are stories of rags-to-riches. People without any property, after coming to politics or Government service for a period of five years are seen driving cars, raising multi-storey buildings. We saw in newspapers a few days

back that a Private Secretary of an ex-Minister was found in possession of one crore of rupees.

**5.00 p.m.**

The existing law to deal with corruption has become irrelevant and inadequate. The Parliament should seriously think of replacing the present law with the most stringent one in order to deal with corruption adequately and expeditiously. In China, those people found guilty of meddling with public funds are executed. Crores of them are being executed. Our laws are not so stringent, but the necessity to bring in stringent laws to deal with corruption has arisen. We, the Members of Parliament, should seriously think of replacing the existing laws with the most stringent ones to deal with the manace of corruption effectively.

This Resolution should receive the support from the whole House and we should find out effective measures to curb it which is eating into the vitals of our society. Thank you.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (PUNJAB): Madam, at the very outset, I would like to welcome this Resolution of Shri Ram Das Agarwal. Shri Agarwalji expressed deep sentiments against an issue which is agitating the minds of the Indians. Both the Houses of Parliament at different points of time have been debating this issue for the last so many years, but the wisdom of the two Houses remained inadequate in throwing up some legislations or raising some political consciousness in the country to fight against this evil of corruption. This Resolution, in fact, touches a very basic issue. As rightly stated by Agarwalji, if the Indian State remains corrupt, the basic foundations of our State like democracy will wither away. This Resolution talks about corruption only, but my colleague from the Communist Party says that some criminal and sectarian elements are also undermining the existence of the Indian State. I wish that this also became a part of this Resolution.

I would like to add one more issue, i.e., political morality which is really causing havoc with our various institutions and we are really moving towards destroying these institutions which we developed in the last thirty years of the post-Independence period. I want to sa something about political morality by sayin something about the land of Gandhiji.

You know, this country witnessed Hajuri Khajuria-Khajuraho scene. People would lik to see whether they are fighting a politic battle of principles. Certain people who are n sharing power and the loot in the Governmer get hijacked in a hired plane and stay in a five star hotel.One would like to know as to wh paid for it. It is a recent event which everybod knows. I would not like to remind you of th other issues of 1977. That is why I was sayin to a friend of mine, Do not go just five-six yea back; the issues will really go back to a lon time-to 1977 when the Government wa breaking up. A very senior leader of Shr Ramdas Agarwal's party went and approache somebody and said, "We are willing t withdraw charges of corruption and th commission of inquiry. You support th Government in the Lok Sabha." Is not this a issue which disturbs more than what the mone exchange does?

SHRI NILOTPAL BASU: Can you wait fc a minute? Is it your contention that it starte in 1977?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA Well, I am not saying that. But it goes back t a long time. It is not confined to: (*Interruptions*)... Corruption is growing fror day one.

SHRI NILOTPAL BASU: There should nc be a cut-off date then.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Th is what I was saying to a friend of mine, not t confine it to just five years.

SHRI NILOTPAL BASU: Let us not delv into a cut-off date.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I ar mentioning an event of 1977. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: He is mentionin 1977 as the cut-off period.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I ar just mentioning an event of 1977 and th political morality. Very recently in U.P. Government was functioning according to th rule of law. The same Mr. Agarwal's party brok

the Government up. Then somebody was made the Chief Minister. After three months they withdrew the support. This is a case of political corruption. Is it not?

SHRI SATISH AGARWAL: No. It is not corruption.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: What is it then?

It is not just money. I am talking of political morality also. It is the political immorality which is the most dangerous thing to a democratic institution. Democracy was functioning. You tried to subvert the functioning of democracy. It is a classic case of destroying democracy. My point is that this Resolution needs to be amended further. Mr. Basu mentioned it and I myself am mentioning the case of political morality and Hajuria and Khajuria and so many other things. They are more dangerous.

I am coming to the basic point. Is not India's political class looking like a ghost of corruption all the time? For example, the securities scam. I think, you need to really think and search your soul when you make charges against individuals. As regards the security scam it was operating earlier. It was a system failure. It started in 1985 and it was at its height in 1989 at which time Mr. Basu's party was also supporting the Government. (*Time-bell*) Madam, I have to have a long time. Do not disturb further. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I am not disturbing. This is not fair. Withdraw your words.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Okay, I withdraw.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We are not going to tolerate this kind of language against the Chair.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): He said, "You are disturbing me." It is an insult to the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Singla, this is not fair. You should be careful in using the language.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am withdrawing. I was disrupted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I have given you nine minutes. I have given only five minutes to others.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am sorry, Madam, mentioning this. I have been noticing the behaviour of this particular Member for the last two weeks. (*Interruptions*)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: He is misbehaving for years together. He is doing like this for the last four years. (*Interruptions*) That is what I am saying. You have been disturbing the proceedings of the House....(*Interruptions*)... You have been doing so for the last four years. ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Singla, correct your figures. ...(*Interruptions*)... He has been in this House only for the last two years.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please cool down. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: He should behave himself. ...(*Interruptions*)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: He should behave himself. ...(*Interruptions*)... He must learn how to behave when in the House. ...(*Interruptions*)... Madam, I am coming to the point. This scam has been occurring since 1985 onwards. It is the economic reforms which discovered that there was a scam. It could be discovered only when the system was opening itself up and when the market forces were opening themselves up. It is only after that you were able to discover that certain people were looting the public sector banks. ...(*Interruptions*)... Please do not disturb me. ...(*Interruptions*)... I am not going to yield. ...(*Interruptions*)... Madam, kindly ask them to sit down. ...(*Interruptions*)... My point is as long as the JPC was there, for a moment the bureaucracy and the administration were punished, the whole Parliament was sullied because they were observing the politician everytime. There was everyday drama of levelling false charges against one politician or the other. So this is the class which we have in this country. In order to grab political power, there was an extensive and false propaganda of corruption without any basis and everytime there is the ghost of scams and scams. So, this is the tragedy which the country is going to

suffer. This is the work of a propagandist party. I do not want to name them. They live only on propaganda. People know this. It is true that there is corruption. I would mention one or two cases. I would like to quote from today's newspaper in which Mr. Basu has mentioned that this corruption would be reduced. Reduced--when? When there is transparency, where there is democracy, when there is accountability and when there is collective thinking. I want to quote today's *Statesman*—Our Mistake-Basu. ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Which Basu? ...(*Interruptions*)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am quoting from *The Statesman*. ...(*Interruptions*)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: He is not a Member of this House. ...(*Interruptions*)... You must substantiate what you are saying. ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Which Basu are you referring to? ...(*Interruptions*)... Which Basu?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Basu, Chief Minister of West Bengal ...(*Interruptions*)... What has happened? The State Assembly of West Bengal remained closed for eleven days. ...(*Interruptions*)... They were looking for; they wanted to know about the report of the inquiry commission which was conducted by the judicial officer of their Government. It was not presented to the elected people of the West Bengal Assembly. They did not have the right to know as to what was contained in that report.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, what is this going on?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am mentioning about corruption. ...(*Interruptions*)... I am mentioning about the *benami* property. ...(*Interruptions*)... I am talking about corruption in West Bengal. ...(*Interruptions*)...

DR. BIPLAB DASGUPTA: You have to give a notice first. ...(*Interruptions*)... Madam, I am on a point of order. Madam, the point which the hon. member is raising has nothing to do with the subject which we are discussing her now. We are discussing about scandals etc. an how to handle them. This is the subjec ...(*Interruptions*)... The hon. member is talkin about what the West Bengal Assembly ha done and what it has not done. Is it proper f the Parliament to discuss the affairs of an Assembly?

I am asking this question, can he do that He is doing this. I am raising a point of orde

SHRI SATISH AGARWAL: I don't think h is discussing the behaviour of the Assembl He cannot discuss the behaviour of th Assembly.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I ar only saying that ...(*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, yo must expunge the proceedings. This is not i the rules of the proceedings of the Hous Madam, I want a ruling from you.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, w want a ruling from you. Can you do it or ca you not do it?

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, we ar prepared to accept everything he speaks in th House (*Interruptions*) but this must not go o like this.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Let there be resolution put properly or a motion be put, som notice or something.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I ar talking about the corruption in the State of We Bengal. Five thousand crores of propert ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SARC KHAPARDE): Mr. Singla, do you want a rulin from the Chair or do you want to talk t yourself? Mr. Basu, what is this? Do you wa a ruling? on top of that there is a cross tal between you and the other side. This is not fai I just would like to draw the attention of th hon. Member—Mr. Singla, you sit down—th Resolution which says,

> "Having regard to the fact that corruption increasing day-by-day endangerir democracy and lowering the political an ethical standards, this House resolves tha

there is an imminent necessity to evolve a mechanism to tackle the problem." We are not discussing any State Assembly here. So please don't discuss any Assembly here.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, I am not discussing the Assembly here.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I am giving you only two minutes.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, You cannot say like this to me.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No, I can say. I think I am here as a Presiding Officer. If a Member is going beyond the time, I have to see.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, you permit me, they are taking away my time.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I have permitted you for 17 minutes, Mr. Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, they are always disturbing me and they are not allowing me to speak. The question was he was raising a point of accountability, some transparency. The report with me is that there was no transparency in the Wakf Board properties. It is the Central lagislation that I am talking about. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Another point of order, Madam. There is a judicial enquiry instituted into this, headed by a sitting judge of the High Court. Now what he is saying is prejudicing the judicial proceedings. How can he refer to something which is totally against the rules of the House?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: After 1988, a Chief Minister with fanfare talked about judicial enquiry.

It took eight years and still it has not come into being. Then what happened? Some marchers were going to the mosque and 100 people were killed in this march. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, please note this. If this is the precedent, this House will ...(*Interruptions*)...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: The judicial enquiry is a cover-up of the misdeeds which are happening.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Can he say that the judicial enquiry is a cover-up? (*Interruptions*) Just a minute. (*Interruptions*)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: You address the Chair.

DR. BIPLAB DASGUPTA: How can you say that the judicial enquiry is a cover-up?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: It is an attempt to cover-up. The Judicial Secretary's report was a cover-up. It was not tabled in the Assembly for 11 days.

DR. BIPLAB DASGUPTA: He is talking about the report. (*Interruptions*)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am coming to the point, Madam. If you don't permit me to speak, they will speak all the time. It is not their monopoly to speak in the House all the time.

SHRI NILOTPAL BASU: You get your facts straight.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Come out with facts. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Speak on the Resolution. (*Interruptions*)

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: I am talking about the Resolution. Don't teach me how to speak. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: You do not know the ethics of the House.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: You don't have any sense of ethics. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Singla, transparency was the biggest casualty at the Centre during the last five years of your Covernment. Transparency was the biggest casualty. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Mr. Singla, I concede your Government's expertise in corruption.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: What about corruption in your own State, West Bengal? You have corrupted the whole State of West Bengal. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: All right. Go on. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I think hon. Members should maintain their cool. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: We will not say anything. Let him talk anything.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: They can speak anything, but when I am speaking, they are so much disturbed.

Madam, I just want to make one point. The people in the country have said: 'No; we surrender; these people cannot be taught any lessons in honesty'. Our mistake was to accept them and hope that they would do the needful. But they are not doing the needful. That is the grievance. (*Interruptions*)

श्री रामदास अग्रवाल: मैडम, मेरा जो प्रस्ताव है, यह दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। कोई मतलब नहीं है इसका। ...(व्यवधान)...

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: अग्रवाल साहब, ये बोलने नहीं देते हैं किसी को।...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: आपका और उनका कुछ मामला है, यह तो हमेशा रहने वाला है। इस प्रस्ताव से इसका क्या संबंध हैं? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Singla, your time is up. I will call the next Member.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Let me finish, Madam. Just two-three points.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): How long would you take to complete making your points?

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Last point, Madam.

It is the contention of Mr. Basu...

SHRI NILOTPAL BASU: I will present you with a mirror, Mr. Singla.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Look at yourself in the mirror first. I will present you with a bigger mirror.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): What is this running commentary, Mr. Basu?

SHRI NILOTPAL BASU: He is addressir me, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SARC KHAPARDE): You are unnecesarily creatir problems.

SHRI NILOTPAL BASU: He is addressir me instead of the Chair, Madam.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: We do I have the right to comment on yo suggestion or not? Do I have the right or not

SHRI NILOTPAL BASU: He should addre the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SARC KHAPARDE): You should tell him that I should address the Chair and not yourself. Yc are not doing that.

SHRI NILOTPAL BASU: I stand correcte Madam.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: think I have a right to comment on h suggestion. he said that depoliticisation w taking place. He suggested that there shou be some kind of a State control on everythin On the other hand, my point is that corrupti is growing because of the presence of a lar number of public sector understakings. First all, we saw the involvement of banks in t securities scam. Then in the case of sugar, t Government was involved. Therefore, n whole contention is, my whole point i Government is the biggest problem. The peo in the country must understand thi Government is the biggest problem. The rc and size of the Government must be reduced the minimum. If the people of India want corruption-free State, the role of t Government must be reduced to the minimu Wherever you find there is corruption, it because Government is the biggest problem

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SARC KHAPARDE): Please conclude now.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: D have the freedom to speak in the House or nc Why am I being interrupted by Membe whenever I want to speak? If they do not all me to speak, I will see that they also do r speak. I have the capability of not letting the to speak. If they misbehave with me, they a responsible for it.

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I seek your protection. (*Interruptions*) I seek for protection.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: What protection? Everytime, you do not allow me to speak.

SHRI NILOTPAL BASU: I seek your protection, Madam. He cannot threaten me like this. This is unprecedented. (*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL: Let him conclude, Mr. Basu.

SHRI NILOTPAL BASU: But Agarwalji, when he is threatening me like this, I have to seek the protection of the Chair. He cannot threaten me like this. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Basu, he also needs my protection. please keep your cool, sit quietly and listen to him so that my job would be more easier. Okay?

SHRI NILOTPAL BASU: All right, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, Mr. Singla, please conclude.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, I would like to make one suggestion here. As I was pointing out, the role and size of the Government must be reduced to the minimum, if we are seriously interested in curbing corruption in India.

The second thing is about the Lok Pal. Myself and my party have been pointing out in the House the immediate need to establish a Lok Pal. This has been pending for long. The Government had promised that they would come up with the Lok Pal Bill. Therefore, let a Lok Pal be established immediately so that the serious problem of corruption could be tackled.

Let the Lok Pal Bill cover everybody, including the Prime Minister. This is my second suggestion.

My third suggestion is, you have to strengthen the political parties. This is where the question of selecting good people come in. As Mr. Agarwal has rightly said, if the political parties are not choosing the right kind of people to represent them in the State Legislatures and Parliament, you will have all kinds of criminals coming in. Therefore, the political parties have a major responsibility in this regard in seeing that they select proper leaders.

This is all I wanted to say, Madam. Thank you.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): मैडम, यह जो भ्रष्टाचार का मामला है। "हरि अनन्त हरि कथा अनन्त" यह एक कहावत है। इसमें हम कितनी भी कथा वाचे परन्तु पता नहीं इसका अन्त कहां होगा? जब भी हम भाषण देने के लिए उठते हैं इस सदन के अन्दर या बाहर तो भ्रष्टाचार को पानी पी-पी कर कोसते हैं और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को सदाचार बनाने की जिम्मेवारी दूसरे की है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ भ्रष्टाचार को कोसने की है। मैडम, भ्रष्टाचार सुरसा की तरह सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। यहां मैं न्यायपालिका पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, मगर उस क्षेत्र में जिस शुद्ध आचरण की उम्मीद करते हैं, जिस नैतिकता की उम्मीद करते हैं, उन क्षेत्रों में वह नैतिकता दिखाई नहीं पड़ती है। मैडम, आवश्यकता है कि सभी दलों के लोग, चाहे वह शिक्षा से संबंधित लोग हैं, चाहे वह न्यायपालिका से संबंधित लोग हैं, चाहे वह राजनीतिज्ञ लोग हैं, सभी क्षेत्रों के लोग आपस में मिलकर बैठें और इस बात पर विचार करें कि इसको खत्म करने के लिए कहां से शुरूआत करनी चाहिए और यह कहां जा कर खत्म होगी, क्योंकि आजकल समाज को आगे बढ़ाने के बदले अपने आपको बढ़ाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है तथा अधिक से अधिक पैसा जमा करना, अधिक से अधिक सुखभोग, आराम की सामग्री जमा करना यह प्रवृत्ति बढ़ गई है और सभी क्षेत्रों में बढ़ी है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ये ऐसा मामला है कि अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो आज सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जो घोटाले हो रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। अग्रवाल साहब इस संकल्प को इस सदन में लाये हैं, यह अच्छी बात है। हम कई अवसरों पर भ्रष्टाचार के बारे में विचार करते हैं और विचार करने के कई मौके आते हैं। मगर बात वहीं की वहीं रह जाती है। हमारी जिम्मेवारी सबसे अधिक है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि हैं। हम राज्य सभा में, लोक सभा में, असेम्बली में, काउन्सिल में आते हैं समाज को एक आश्वासन देकर, एक जिम्मेवारी लेकर आते हैं कि हम इस देश को, समाज को आगे बढ़ायेंगे। हम समाज में जो गन्दगी है उसकी सफाई करेंगे और उसकी सफाई करने में हम मदद करेंगे, मगर हम ऐसा नहीं कर पाते, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाये हैं और इसे

स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। जो कुछ हो रहा है उसको खुले दिल से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसकी जिम्मेवारी दूसरे लोगों पर नहीं छोड़ कर के, इसकी जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए।

मैडम, जो कुछ हो रहा है यह बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। जैसे अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि स्व. लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग इस देश में पैदा हुए हैं। कई लोग इस देश में पैदा हुए जिन्होंने समाज में एक उदाहरण कायम किया है और समाज को दिशा-निर्देश दिया है। उनकी चर्चा हम जरूर करते हैं, भाषणों में उनकी चर्चा करते हैं, किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं मगर ऐसा लगता है कि उसका कोई असर नहीं हो पा रहा है। मैडम, यह बहुत आवश्यक है कि समाज में हर व्यक्ति अपने आपको देखने की कोशिश करे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करे। सभी साथियों और सभी व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि वे सर्वप्रथम अपने अंदर झांककर देखें और अपने आप से इस बात को शुरू करें और तब दूसरों तक यह बात ले जायें। गांधी जी सादा जीवन व्यतीत करते थे तभी वे दूसरों को सादा जीवन व्यतीत करने को कहते थे, दूसरों को प्रोत्साहित करते थे। सफाई हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी और अपने आप से सफाई शुरू करके फिर समाज की सफाई करनी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अग्रवाल साहब का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस रेजोल्यूशन में जो कुछ कहा गया है और हमने अपने भाषणों में जो कुछ कहा है उस पर चलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Jalaludin Ansari not present.

Yes, Mr. Minister.

Just a minute, Mr. Minister. I am sorry.

Dr. Radhakrishna Murty is there.

I am sorry, Dr. Radhakrishna Murty. I could not see you there.

SHRI SATISH AGARWAL: Up to what time will the debate go on?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He is the last speaker now... (*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL: When will the Government respond? Shall we conclude it today?

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SARO KHAPARDE): The time is up to 5-42 PM. I started around 3-15 PM. It will go on for ten t fifteen minutes more.

SHRI SATISH AGARWAL: I don't doub your capcity to calculate time. 5-42 PM is al right.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SARO KHAPARDE): Thank God. At least you don doubt my capcity to make calculations an things like that.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (ANDHRA PRADESH): Madam, If they don have the patience, I will retire.

Madam, I am a ten-day infant in this Hous During this period I have seen that a lot of hea has been generated everyday. I feel a littl different to rise, but, with the moral suppor given to me by some of my colleagues here, want to say a few words.

I want to speak on the operative part of th Resolution. Its content is very sensitive an very general in nature. Quite a lot of it has bee said about corruption, the series of scams etc etc. But, I am afraid, the only thing that wa not mentioned is the trickel-down effect th political corruption in this country had on th abodes of God, the temples of our country Leave it alone.

The first thing I would like to mention i about the evolution of corruption itself. Th first stage was when our great national leader were ruling the country. Pt. Nehru said tha every blackmarketeer would be hanged on th nearest lamp-post. That stage was over.

We come to the second stage wher politicians had no direct relationship wit corruption, but it was indulged in indirectl through agents.

In the third stage it was said, "Corruptio is universal. Therefore, we need not be afrai of indulging in corruption directly also."

We have now reached the fourth stage wher mantriks, mafias and tantriks have come int the field, and the money got through corruptio has gone into Swiss banks etc. etc. The firs point I would like to mention is the lack o transparancy, which is the root cause of the

political corruption. The so-called Official Secrets Act is a guise for so many scandals. It may be Defence purchases, it may be sugar scandals, it may be telecom scandal, it may be urea scandal and so on. I am not going into all those things. When Shri V.P. Singh took charge in 1989, he declared that his Government would be an open Government, but, unfortunately, it was a short-lived Government. Again we got a closed Government. The great democracies in the globe like France, Italy, South Korea, Japan and some of the autocracies in South- East Asia have been experiencing political corruption, but they have their own methodology wherein their Ministers and PMs were tried and severely punhished. But, unfortunately, in our country we have enjoyed almost full freedom and have been very generous and affection of our people was partially blind to what was going on. Probably they took it lying down as the necessary or inevitable evil, until we have this judicial activism. Now since that judicial activism is available—though we have to take it with a pinch of salt—it is probably unavoidable.

The second point I would like to make is regarding electoral corruption. I do not know how many of us have come to this House without the money power. Somebody has tried to take care of it and the Election Commission has tried its level best to get rid of this factor, but there was a hue and cry. To the extent he did it, we appreciate it. Probably it has to be taken to its logical conclusion. Electoral reforms have to come in and the Legislature has to think of radical electroal reforms to curb corruption and money power in elections.

The third point is that money power has come to rule our country at the corporate level, at the land- lord level. Money bags wait in the Five-Star hotels whenever a Government is going to change to instal a Government of their liking both at the Centre and in the States. It is a great testimony to the democracy that we are enjoying here. Our Constitution lays down equitable distribution of wealth and also of means of production, but we have yet to see that. Probably till we fulfil that obligation of our Constitution, this part of corruption would not be changed.

Our tax laws are very slack. We have not had our land reforms. They are only on paper. Money is also controlling our Fourth Estate. So many things are planted. People with crime records are shown as saints. They picturse even devils as saints and people come to believe them.

Then coming to administrative level, there is a lot of interference and political patronage. We have our bureaucracy, which has no backbone and which is lying low and is bending backwards. Probably you have seen T.V. serials like 'Yes, Mr. Minister' and 'Yes, Mr. Prime Minister'. We have reached a level of the politician—bureaucrats-criminal nexus. Now, we have come to a stage wherein we have to fight it at the legislature level at the judiciary level as well as at the public level. The Lok Pal, the Lok Ayukta, can go into hibernation, as long as we do not have a political will, a strong political will. That is what is required now.

The second thing, as I said, is the equitable distribution of wealth so that the money power does not rule this country.

The third thing is that the education level of our population should be raised so that the commonman's awareness increases and he does not have to, as Members have pointed out, elect the criminals into the legislatures and the highest bodies. An example of our national leaders is there for us. *(Time bell)* Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Are you angry with the Chair?

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: With due respect to the Chair, I want to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please take two more minutes.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: Okay, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): When I rang the bell, it was just a warning to you that you should conclude in the next one or two minutes. Please go ahead and take two more minutes.

SHRI ASHOK MITRA: Others should emulate it.

श्री मोहम्मद सलीम: शिकायत होती रहती है कि घंटी कोई सुनता नहीं है।

†الشری محمد سلیم: شکایت ہوتی رہتی ہے کہ گھنٹی کوئی سنتا نہیں ہے۔

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): देखिए जब आप ठीक से बोलते हैं, और उसको सुनते हैं तो लगता है दो मिनट और आपको देने चाहिए।

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: For example, our great national leaders are there. The spirit of our national movement is there. We pay only lip service to it. We give lectures from the platforms. We follow them by default. So, ethical uprightness is the thing that is required now along with other measures which I had enumerated. "Satya Meva Jayate" is inscribed everywhere in our country and I wish that is followed correctly by every individual, particularly by politicians. Thank you, Madam.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): Madam Vice-Chairman, the Resolution moved by Shri Ramdas Agarwal is general in nature. About ten Members have participated in the discussion. Mr. Ramdas Agarwal who moved the Resolution made a very lengthy speech. He spoke for about 45 minutes. I only assure and confirm that we condemn corruption and corrupt practices. It is in the Common Minimum Programme of this Government that we would give a corruption free and a clean Government. So, I can assure the hon. Member that we stand for a corruption-free Government. But its eradication is a continuing process. He was trying to say as if from the Independence days, the Government had not taken any steps to eradicate corruption. It is not correct to say that the Government has not taken any steps. Of course, we need some more mechanism. I do agree and we can feel that we need some more steps to check corruption at the high level. The Government has taken a number of steps. The Government has always been alive to the need for eradication of corruption at all levels of the administration. The drive against corruption in public services is a continuing process and to achieve this objective an elaborate vigilance system has been established. Primarily, it is the Secretary of the Department, Head of the Department who is responsible for checking corruption in his Ministry and his Department. There is a Central Vigilance Commission and a Central Bureau of Investigation and two other agencies. Apart from these, there is an Administrative Vigilance Commission in the Ministry of Personnel and Public Grievances and Pensions.

With a view to eradicating corruption from the public life, the Prevention of Corruption Act was originally enacted in 1947. This Act has been further strengthened by the enactment of the Prevention of Corruption Act, 1988 which is more comprehensive. The new Act of 1988 provides for widening the scope of definition of the terms "public servants" including the office bearers of the registered cooperative societies engaged in agriculture, industry, trade or banking, etc. A provision has been included in this Act for setting up of special courts to try the offenders under this Act. In this Act, there is an incorporation of offences under section 161 to 165(a) of the IPC. In this Act, there is an incorporation of definition of the term "known sources of income" to mean only lawful sources of income.

Mr. Bisi, referred to the Santhanam Committee report. The Central Vigilance Commission, set up in 1964 following the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption, popularly known as the Santhanam Committee, has jurisdiction and powers in respect of matters to which the executive powers of the Union extend. It advises the Government on the further action to be taken against delinquent public servants besides assisting the Government in ensuring that complaints of corruption or lack of integrity on the part of public servants are given prompt and due attention. Any disagreement with the advice of the Commission is required to be explained to the Parliament by the Government. The Common Minimum Programme announced by this Government has reiterated its commitment to a corruption-free and clean administration. To this effect, they have made it very clear that the Bill to set up the Lok Pal

†Transliteration in Arabic Script.

will be introduced in the Budget Session. The Bill will cover all the Ministers, Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers and Members of Parliament also. Already we have a Draft Bill. It has been sent to the Law Ministry. It is at the stage of printing by the Ministry of Law. I think, as far as I know, it has actually gone to the legislative section and it is at the stage of printing.

The endeavour of the Government is to have the Bill introduced at the earliest after following the prescribed procedure. While hon. Members will get ample opportunities to suggest suitable modifications after the Bill is introduced in Parliament, they are welcome to give their suggestions so that they may be taken into account while giving a final shape to the proposed Bill.

Almost all the Members have made one point, that is, the mechanism will be Lok Pal. It has been debated and discussed in both the Houses of Parliament on a number of occasions. The concept of Lok Pal has been discussed for about three decades now. In 1966, the Administrative Reforms Commission had recommended that the two institutions, Lok Pal and Lok Ayukta, should be set up covering the Central Government and the State Governments to look into complaints against public servants regarding injustice, maladministration and corruption. In pursuance of that, Lok Pal Bills were introduced in 1968, 1971, 1977, 1985 and 1989 but could not be enacted. During the December, 1995 Parliament Session, while answering a supplementary to Starred Question No. 142 in the Lok Sabha, the Minister of State for Personnel mentioned that on the basis of the informal consultations held with certain leaders of political parties to work out a consensus on this issue, it was decided that the Lok Pal Bill, 1985 would be redrafted taking into account suggestions made by Members in the House on 6.12.1995, besides effecting the necessary technical revisions as may be required. A note with a Draft Bill was submitted to the Cabinet which, however, deferred a decision then.

The Common Minimum Programme announced by the present Government has reiterated its commitment to a corruption-free administration. It also states that a Bill to set up a Lok Pal will be introduced in the Budget Session of the Lok Sabha. The Bill will cover the office of Prime Minister as well. All the Members of Parliament will be required to declare their assets yearly before the Lok Pal. So, we are committed to bringing in the Lok Pal Bill at the earliest. If members have any suggestions to make, they can give their suggestions. They will definitely receive due consideration and, if need be, will also be incorporated in the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Thank you very much, Mr. Minister. Agarwal Ji,..... (*Interruption*).

SHRI MD. SALIM: Madam, I have a point to raise. How long will we take for a Private Member's Business? It is normally two and a half hours. Now you are going beyond that. It is not fair. Normally it is from 2.30 to 5 p.m. This time, we did start a little late because the reply of Mr. Yadav was delayed. But I want to know from you for how long we will continue and how much time we have taken already.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We started around quarter past three and the debate went on up to 5.42 p.m. Now, the Minister has replied and the hon. Member is going to say something about it. And therefore, you know the procedure. It will take hardly ten minutes.

SHRI MD. SALIM: Madam, the Session is continuing for another fortnight at least and we are getting the next Friday and the one next to it also. I do not think that we should continue with this now. We should rather have the statement of the Minister now. He can reply. This can be taken up later. We should not set a bad precedent. Normally, we have two and a half hours for Private Members' business.

This is the normal convention. This is how we have been doing this. (*Interruptions*) now, I want you ruling, Madam. (*Interruptions*) I think we should finish the Private Members' Business now. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister has given his reply to the Resolution. Now, the hon. Member is going to speak and thereafter, we will take up the statement of the Home Minister. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: Madam, we are stretching the Private Members Business too far. My apprehension is that this will create a precedent, and later on, we will find it difficult to manage.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) Who should be blamed for that?

SHRI MD. SALIM: He took more than one hour to finish his speech. (*Interruptions*)

THE VICE CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He hardly spoke for thirty-five minuts. He was within his time. (*Interruptions*) What about the other Members? (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: That means we are to be blamed. (*Interruptions*) The Private Members' Business should not continue any more. We have already crossed that limit. (*Interruptions*) I have not pointed it out earlier to you. But now I am pointing it out to you that you should take a decision. Mr. Agarwal can reply later on. It is not that his Resolution is going to be finished. He will have an opportunity to speak. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, Mr. Agarwal has to reply.

SHRI MD. SALIM: He can reply on the 2nd August, 1996 also. There is no problem. The time allotted for the Private members' Business has exhausted. Now, you can ask the Minister to make a statement.

He is sitting here for making a statement. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): It is a question of only ten minutes now. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: The House will sit beyond six o' clock. Is that your suggestion, Madam?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): That is not my suggestion. Ultimately, you have to decide it whether the House will sit beyond six o'clock or not. (*Interruptions*) If you are not in a mood to sit beyond six o' clock. I have no objection. But I am not going to run the House in this manner. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: The Minister will not reply today. He will not participate. He can lay the statement on the Table of the House. That is my submission. (*Interruptions*)

**श्री रामदास अग्रवाल:** उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि मैं इस बहस के उपर अपना उत्तर अगले समय अर्थात् 2 अगस्त को दूं। मैं समझता हूं कि इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं फिर जैसा आप का आदेश मिलेगा, उस के अनुसार काम करूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** मेरा आदेश नहीं, मुझे तो आप के आदेश से हाउस चलाना है।

**श्री रामदास अग्रवाल:** माननीय सदस्य कुछ आपत्ति कर रहे हैं।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):** देखिए, सदस्य ने तो आपत्ति उठायी है और उस आपत्ति के हिसाब से आप को अगले समय दो अगस्त को बोलना है। तो मैं तो यहां पर बैठी हूं, सदस्य मुझे जो कहेंगे, उस मुताबिक मैं सदन चलाउंगी। आप मुझे बता दें, इस समय मत चलाइए इस विषय पर, अगले विषय लीजिए मैं अगला विषय ले लूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है।

So, I can take up the statement of the Home Minister now. Mr. Home Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDARJIT GUPTA): Madam, the other day, I had stated in the House that after I had visited Bihar, particularly the villages where this massacre had taken place. I would be able to come back to the House with some more information and detials. I am sorry there has been a little delay in preparing the statement which is rather lengthy, I am afriad. It is about 4 1/2 pages. So, if you with, I will now make the statement and if you so desire, I can lay it on the Table of the House also.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Salim, I woud like to take advice from you now because I won't be able to give any ruling.

SHRI MD. SALIM: Madam, you can take the sense of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I am putting a question to you. You are also an hon. Member of this House.

SHRI MD. SALIM: Madam, this is a lengthy statement (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): From today onwards, I have to take advice from everybody. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: Madam, as far as I am concerned, I should say that it should be laid on the Table of the House. Today is the fag end of the week-end.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Why?

SHRI RAMDAS AGARWAL: If the clarifications were to be taken up later on, then it should have been made on Monday instead of today. Then what is the value of this statement?

He should have given it on Monday itself.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I would be obliged, Madam, if you give you consent for me to lay it on the Table of the House because I am to repeat the same exercise in the Lok Sabha within five minutes or less than five minutes. There is a bit of a problem. The statement can be discussed; clarifications, questions and all that can be taken up later.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Okay. You can lay it on the Table of the House..... (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बोलिए, बसु जी।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, in this House we have a right to seek clarifications. That should be there, but given him the next opportune time to give clarifications .... (*Interruptions*)...

SHRI RAMDAS AGARWAL: Madam, he has to present himself in the Lok sabha immediately, within five minutes. How can clarifications be sought in five minutes? ...(*Interruptions*)...

SHRI MD. SALIM: Subject to the availability of the Minister we can seek them on Monday or Tuesday? ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sufficient time should be provided for seeking clarifications.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मिस्टर सलीम, मुझे क्या बोलने के लिए आप कह रहे हैं। मैं तो जो आप कहेंगे वही करूंगी। हर वक्त चेयर कुछ कहती है, आप लोग कुछ कहते हैं। अगर आपको इनकन्वीनिएण्ट होती है तो मैंने तो आर्डर दे दिया है, अनुमति दे दी है मंत्री जी को, कि आप स्टेटमेंट जो है टेबल पर रखिएगा। अगर आपको कलेरिफिकेशन पूछनी होगी तो आप लोग बाद में पूछिएगा। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है।

---

## STATEMENT BY MINISTER

### Incident of arson and massacre of people in Bhojpur District of Bihar on 11th July, 1996

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Madam, I lay a statement on the Table of the House on the incident of arson and massacre of peope in the Bhojpur District of Bihar on 11th July, 1996. ...(*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, the point is preceisely raised that you can take the sense of the House, but so far as I am concerned, I would not like to sit beyond six. So, clarifications can be sought on some other day, I mean, on the availability of the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Agarwal, what do you think?

SHRI RAMDAS AGARWAL (Rajasthan): Madam, I think that his statement should not have been placed on the Table of the House today if there was no time to seek clarifications. But since it has now been laid on the Table of the House, it is better-because this matter is also very important and it is necessary to seek clarifications right now; otherwise, its importance would be lost.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): डाक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे।

DR. RANBIR SINGH (Uttar Pradesh): Madam, clarifications can be sought later.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I am told by the Secretariat that Monday is a Budget day. So, we can seek clarifications on Tuesday. Will that be all right? Mr. Minister, is it convenient for you to give clarifications on Tuesday?

SHRI RAMDAS AGARWAL: Then what is the use of laying this statement today?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I do not want to make any comment from here. I think we can adjourn the House now. I adjourn the Houe till 11.00 A.M. on Monday.

The House then adjourned at fifty eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 22nd July, 1996.

---